CNews सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-239
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सिटी चीफ

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, बुधवार 04 दिसम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

सुविचार

'सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है।'

पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर स्वर्ण मंदिर में जानलेवा हमला, गोली चलाने वाला हिरासत में

पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार सुबह करीब 9.30 बजे जानलेवा हमला हुआ। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में उनके ऊपर फायरिंग की गई, लेकिन वह हत्या के प्रयास में बाल-बाल बच गए। हमले के वक्त बादल स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर सेवा कर रहे थे। तभी अचानक गोली चलने से स्वर्ण मंदिर में अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

दरबान बनकर सेवा कर रहे थे सुखबीर बादल- बता दें कि अकाल तख्त द्वारा सुनाई धार्मिक सजा काटने के लिए सुखबीर बादल ने मंगलवार को गुरुद्वारे में सेवा कार्य किया। इस दौरान उन्होंने बर्तन धोए और टॉयलेट भी साफ किया था। आज सजा के दूसरे दिन सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर सेवा कर रहे थे। तभी हमलावर ने पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चलाई। हालांकि, सुखबीर सिंह बादल के आसपास खड़े उनके समर्थकों और सुरक्षाबलों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया, जिससे सुखबीर सिंह बादल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

हमलावर से पूछताछ जारी, पिस्तौल बरामद हुई- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को तत्काल सुरक्षा घेरे में ले लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान वहां मौजूद सेवादारों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौरा है, जो दल खालसा से जुड़ा हुआ है। उससे पूछताछ कर हमले का मकसद पता किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि स्वर्ण मंदिर में सभी गेट पर मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद हमलावर कैसे अपने साथ पिस्तौल अंदर ले गया। इस घटना से स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। सुखबीर बादल पर हमले के चश्मदीद अकाली दल नेता दलजीत चीमा ने बताया- सबसे पहले, मैं गुरु नानक देव जी का धन्यवाद करता हूं। जाको राखे साईंया, मार सके न कोई। सेवा कर रहे सेवकों की रक्षा हुई। सुखबीर सिंह गुरु रामदास द्वार पर चौकीदार के रूप में बैठे थे। उनकी दिशा में गोली चलाई गई... गुरु नानक देव जी का शुक्र है कि उन्होंने अपने सेवक को बचा लिया। यह एक बहुत बड़ी घटना है। पंजाब को किस दिशा में धकेला जा रहा है? मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप पंजाब को कहां ले जाना चाहते हैं? हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। मैं सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता हूं। यदि उन्होंने तुरंत कदम नहीं उठाया होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

अकाली दल ने की न्यायिक जांच की मांग-शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस जानलेवा हमले की तह तक जाना बेहद जरूरी है। हम अपनी सेवा जारी रखेंगे। यह घटना हमें हमारे मार्ग से हटा नहीं सकती। सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलने से पंजाब की राजनीति में हलचल है। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह से पूछे तीखे सवाल

किसानों से किए वादे क्यों पूरे नहीं हुए?

उपराष्टपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दों को उठाते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए। उन्होंने खासतौर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए पूछा कि देश की वैश्विक मंच पर बढ़ती साख के बावजूद किसानों से किए गए वादे क्यों पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा- नीति-निर्माण सही दिशा में नहीं है।

धनखड़ ने कृषि मंत्री से किए सीधे सवाल- उपराष्टपति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में कहा- कृषि मंत्री, आपके लिए हर क्षण महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे बताएं, किसानों से क्या वादा किया गया था? वो वादा क्यों पूरा नहीं हुआ? वादे को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पिछले साल आंदोलन हुआ था, इस साल भी आंदोलन हो रहा है। समय का चक्र घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा- पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत बदल रहा है। पहली बार मुझे लग रहा है कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य है। भारत पहले कभी विश्व में इतनी ऊंचाई पर नहीं था... जब यह सब हो रहा है, तो मेरा किसान चिंतित और पीड़ित क्यों है? किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा असहाय है। उपराष्टपति के सवालों पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चौहान, करीब 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने।

देश में बढ़ रहे किसानों के प्रदर्शन- उपराष्टपति के बयान ऐसे समय में आए हैं जब देशभर में किसान आंदोलनों में तेजी देखी जा रही है। सोमवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नोएडा से दिल्ली की ओर मार्च किया, जिससे दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में यातायात बाधित हुआ। किसान नए कानूनों के तहत गारंटीकृत मुआवजा और लाभ की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, पिछले साल फरवरी से पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। किसान प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। उन्होंने समस्याओं का समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।

देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए

अब महायुति की बैठक में होगा मुख्यमंत्री का फैसला

महाराष्ट्र में महायुति सरकार गठन के लिहाज से बुधवार (4 दिसंबर) का दिन बेहद अहम है। नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ऑब्जर्वर के तौर पर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के नाम का भी आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार (5 दिसंबर) को शाम 5 बजे होगा।

शिंदे के साथ बैठक मेंशाह का रवैया सख्त इसबीच, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से जुड़ा नया खुलासा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट्स में दावा किया है कि शिंदे ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने महज 6 महीने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, खबरों के मुताबिक, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व ने 28 नवंबर की बैठक में मिले इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

शिंदे को बीजेपी लीडरशिप से मिला स्पष्ट जवाब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एकनाथ शिंदे से कहा कि अगर वह बीजेपी अध्यक्ष के स्थान पर खुद को रखकर देखें, तो क्या वह बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ देते। इस सवाल पर शिंदे जवाब नहीं दे सके। बीजेपी लीडरशिप ने स्पष्ट रूप से कहा कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त करने का कोई सिस्टम नहीं है। पार्टी ने इसे प्रशासनिक तौर पर गलत और गलत मिसाल कायम करने वाला फैसला करार दिया है।

बीजेपी का फोकस- SÁC बहुमत के बाद दबाव नहीं बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद के कथित वादे, जिसमें शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, अब प्रासंगिक नहीं हैं। पार्टी का तर्क था कि महायुति ने 288 में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी बहुमत के करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद को साझा करना सही फैसला नहीं होगा। हालांकि, महाराष्ट्र में पिछले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तालमेल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

बैठक में कौन-कौन था मौजूद? महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हुई इस अहम बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी शामिल थे।

छत्तीसगढ़ में भूकंप के तेज झटके

बस्तर संभाग के कई जिलों में महसूस किए गए, डरे सहमे घरों से निकले लोग

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 7:32 के करीब भूकंप के झटके महसूस किया गया। दोरनापाल, कोंटा के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकले। वहीं भूकंप से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। सुकमा सहित दोरनापाल, कोंटा, गादीरास सभी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं बीजापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा नारायणपुर में एक सैकेंड भूकंप आया। भूकंप का केंद्र तेलंगाना के भद्राचलम में था। वहीं भूकंप के झटके की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 5.3 आंकी गई है। भूकंप में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इस भुकंप का असर बस्तर संभाग के कई इलाकों में देखा गया है।

अनोखी सजा: युवक ने की मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना

अदालत ने सुनाया फैसला- लगाओ 50 पौधे

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में दोषी युवक को 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे लगाने की सजा सुनाई है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ ने 15 दिन के भीतर पौधारोपण करने का निर्देश दिया। वन विभाग के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे युवक को उपयुक्त स्थान और पौधों की जानकारी प्रदान करें। न्यायालय के खिलाफ की थी टिप्पणी यह मामला मुरैना जिले के संबलगढ़ का है। त्रिवेणी नगर, जयपुर निवासी राहुल साहू पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर न्यायालय और अपनी पत्नी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। इस मामले में न्यायालय ने राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही पेश हुआ। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने अधिवक्ता आदित्य संघी से सुझाव मांगा। उन्होंने युवक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे प्रतीकात्मक और सुधारात्मक सजा देने की बात रखी। इसके तहत भंवरताल पार्क में पौधारोपण का प्रस्ताव रखा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। युवक को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी गई।

होटल में तंदूर जलाने पर रोक, लगेगा इतना जुर्माना

भोपाल में वायु गुणवत्ता सुधारने की कवायद

भोपाल। होटल रेस्टोरेंट में अगर तंदूर जलाया तो तीन हजार रुपए जुर्माना होगा। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसके संबंध में आयुक्त नगर निगम ने बैठक में शहर के सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिए है। समझाइश देने पूरे शहर में ऐलान किया जाएगा। बैठक के बाद निगम अमले ने शहर भर में होटलों पर कार्रवाई कर रात तक लगभग 45 हजार जुर्माना कर 23 प्रकरण तैयार किए। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए हुई बैठक में कमिश्नर नगर निगम हरिन्द्र नारायण ने अनाधिकृत ईंधन के उपयोग पर पाबंदी के निर्देश दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट में तंदूर या अलाव में अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो जुर्माने की कार्रवाई होगी। जोन स्तर पर जांच के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जोन क्रमांक-8 के वार्ड 27 में रेस्टोरेंट संचालक पर तीन हजार का जुर्माना हुआ। तंदूर के उपयोग पर कार्रवाई की गई।

मोहन कैबिनेट की बैठक आज.... विदेश से निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ के प्रस्तावों पर होगी चर्चा

मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार (4 दिसंबर) को होगी। मंत्रालय में होने वाली बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उद्योग विभाग से संबंधित रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

इन मुद्दों पर होगा विचार-विमर्श

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम मोहन यादव अपने मंत्रियों को जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ के प्रस्तावों की जानकारी देंगे। सीएम निवेश प्रस्तावों को साकार करने के लिए उद्योग विभाग से संबंधित रियायतों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार-विमर्श होगा। एमपी में विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं।

सीएम श्रमिकों परिवारों को देंगे बड़ा तोहफा

सीएम मोहन यादव बुधवार को श्रमिकों परिवारों को बड़ा तोहफा देंगे। ष्टरूसिंगल क्लिक से 10236 श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। सीएम मंत्रालय में अपने कक्ष से ही संबल योजना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह सहायता श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। पहली बार आधार से लिंक किए गए श्रमिक परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। बता दें कि इस योजना में अब तक 1 करोड़ 75 लाख 22 हजार श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं। 2 लाख 57 हजार 470 श्रमिक परिवारों को अंत्येष्टि सहायता मिल चुकी है। 2 लाख 89 हजार 791 परिवारों को अनुग्रह सहायता प्रदान की जा चुकी है।

चलो लालबाग: बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में इंदौर में सभी संगठन हुए एकजुट, आज आधे दिन शहर बंद

इंदौर में लगे पोस्टर...ना पोहा ना चाय बांग्लादेश हाय-हाय

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आव्हान पर बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों के चलते बुधवार को इंदौर में आधे दिन का बंद रखा गया है। इस बंद के लिए सभी व्यापारी संगठनों ने लिखित सहमति दी है। लालबाग से कलेक्टोरेट तक आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। सत्तारुढ़ भाजपा ने भी इस बंद को अपना पूरा समर्थन दिया है और सारे जनप्रतिनिधि आधे दिन का बंद करवाने की मुहिम में शामिल हो गए हैं और सभी संस्थाओं से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस बंद को सफल बनाएं। भाजपा के सभी सहयोगी संगठन भी इसमें जुटे हैं और चलो लालबाग का नारा दिया जा रहा है, जहां पर सर्व हिन्दू समाज द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। सकल हिन्दू समाज की रैली व ज्ञापन कार्यक्रम को इंदौर के समस्त धार्मिक, सामाजिक ,व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के साथ सकल हिन्दू समाज का समर्थन मिला है। छप्पन दुकान पर अलग-अलग जगह मंगलवार को पोस्टर लगाए। इसमें एक सवाल उठाया है आखिर कब तक? साथ ही लिखा है बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में ना पोहा ना चाय बांग्लादेश हाय-हाय।
भारत को आवाज उठाना होगी बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों द्वारा लगातार किए जा रहे अत्याचार से पूरे देश में रोष है। व्यापारी संघ अध्यक्ष गुंजन शर्मा के मुताबिक दुनिया में जहां भी हिंदू मुश्किल में होगा भारत को आवाज उठाना होगी। जो अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है। उसे रोकने के लिए आम और खास का समर्थन जरूरी है। हम भी उस समर्थन में बाजार को दोपहर 1 बजे तक बंद रखेंगे। हमने एक ही स्लोगन दिया है ना पोहा-ना चाय बांग्लादेश हाय-हाय। यहां चाय की टपरी भी समर्थन में बंद रहेगी।

जनप्रतिनिधियों ने भी रैली को दिया समर्थन
सांसद, विधायक से लेकर वार्ड पार्षदों तक ने जन आक्रोश रैली को समर्थन दिया है और एक हैं तो सेफ हैं का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। इंदौर चावल व्यापारिक संघ के सचिव सुशील मेहता के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक सभी सदस्यों की दुकानें बंद रहेंगी और रैली में भी शामिल होकर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव क्लाथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के मंत्री कैलाशचंद्र मूंगड़ के मुताबिक बुधवार को सभी व्यापारी संगठनों के साथ एसोसिएशन भी 1 बजे तक के बंद में शामिल रहेगी और लालबाग से निकलने वाली आक्रोश रैली में भी कारोबारी शामिल रहेंगे।
इंदौर चांदी-सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल रांका का कहना है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अत्याचार, लूट-पाट की घटनाओं से सराफा के सभी व्यापारी भी आक्रोशित हैं और भारत सरकार से मांग की गई है कि बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग से अविलंब कार्रवाई करते हुए हिन्दू समाज की सुरक्षा की जाए।
अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सराफा बाजार के सभी व्यापारी 1 बजे तक के बंद में शामिल हैं। वहीं अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हमारी कार्यकारिणी की बैठक में बांग्लादेश में हिन्दू समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं पर सभी सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया और 4 दिसम्बर को सर्व हिन्दू समाज की रैली को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते सीतलामाता बाजार, खजूरी बाजार, स्कूटर पार्ट्स विक्रेता, सियागंज किराना होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन, अपोलो टॉवर विक्रेता संघ, पाइप एंड सेनेटरी, इंदौर टाइल्स मर्चेंट, इलेक्ट्रीक मार्केट, इंदौर मशीनरी टूल्स, मप्र दाल-दलहन संघ, इंदौर केमिकल, इंदौर कन्ज्यूमर प्रोडक्ट, मल्हारगंज व्यापारी एसोसिएशन सहित सभी व्यापारिक संगठनों ने 1 बजे तक अपनी दुकानों, दफ्तरों, संस्थाओं को बंद रखने का निर्णय लिया है। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक धीरज खंडेलवाल ने इंदौर के सभी शॉपिंग मॉल को भी 1 बजे तक बंद रख सहयोग देने की अपील की है। वहीं शहर के केमिस्ट दुकानदारों के एसोसिएशन ने भी आधे दिन के बंद का समर्थन किया है। इधर, शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदिवे का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिन्दुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, जिससे सभी उद्वेलित हैं, जिसके चलते यह आधे दिन के बंद के आव्हान में शहर के सभी संगठनों ने सहयोग देने का भरोसा दिलाया और लिखित में अपनी सहमति भी प्रदान की है।

तीसरी मंजिल से कूदने के डेढ़ माह बाद छात्रा ने प्रेमी पर दर्ज कराया केस

दीपेश जैन, आरोपी

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। विजयनगर इलाके में 17 अक्टूबर 2024 को एक निजी कॉलेज की एमबीए छात्रा तीसरी मंजिल से गिर गई थी। शुरुआत में उसने चक्कर आने की बात कही थी लेकिन डेढ़ महीने बाद छात्रा ने अपने प्रेमी दीपेश जैन के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कराया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि कॉलेज के दौरान उसकी दीपेश से पहचान हुई थी, जो उसका सीनियर था। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती और प्रेम संबंध बने। दीपेश ने शादी का प्रस्ताव रखते हुए भरोसा दिलाया था कि वह अपने माता-पिता को मना लेगा। सितंबर 2022 में उसने छात्रा को एक किराए के फ्लैट में बुलाया और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने कई बार ऐसा किया लेकिन हर बार शादी की बात को टालता रहा।

माता-पिता नहीं हैं शादी को तैयार
छात्रा के अनुसार, दीपेश ने उसे अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल किया, जिससे उसे भरोसा हुआ कि शादी होगी। लेकिन 13 अक्टूबर 2024 को दीपेश ने बताया कि उसके माता-पिता जातिगत कारणों से शादी के लिए राजी नहीं हैं। 17 अक्टूबर को छात्रा दीपेश से मिलने पहुंची, जहां दोनों के बीच बहस हुई। दीपेश ने स्पष्ट कर दिया कि वह न तो शादी करेगा और न ही संबंध रखेगा। उसने अपशब्द कहे, जिससे आहत होकर छात्रा छत पर गई और विवाद के दौरान उसने छलांग लगा दी।

विजयनगर थाने में दर्ज कराई शिकायत
छात्रा ग्राउंड फ्लोर पर शेड पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। दीपेश ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद छात्रा ने बताया कि चोटों और डॉक्टरों की सलाह के कारण वह तुरंत पुलिस में शिकायत नहीं कर सकी। ठीक होने के बाद, उसने माता-पिता के साथ विजय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दीपेश के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच चल रही है। पीड़िता ने आगे बताया कि 17 अक्टूबर को वह फिर दीपेश से मिलने पहुंची। दीपेश ने यहां बात करने से इनकार कर दिया। कहा कि तुमसे बात नहीं करना और न ही शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे साथ टाइप पास कर रहा था। दोनों में जमकर बहस हुई। पीड़िता अपनी मां को कॉल करने टैरेस पर गई। पीछे से दीपेश आ गया। उसने अपशब्द कहे। दोनों के बीच झूमाझटकी हुई। इसी बीच वह नीचे कूद गई। जिससे कमर और अन्य जगहों पर चोट लगी। दीपेश ने ही उसे लोगों की मदद से वीके अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह दी इसलिए थाने पर शिकायत नहीं कर पाई। ठीक होने के बाद माता-पिता के साथ थाने आकर शिकायत की।

हिरण का शिकार कर मांस ले जा रहे थे मुंबई, तीन तस्कर गिरफ्तार

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर के समीप पीथमपुर में तीन लोगों को हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। आशंका है कि देवास, सतवास की तरफ काले हिरण का शिकार कर तस्कर मांस को मुंबई की तरफ बेचने जा रहे थे। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मांस किस जंगली जानवर का है। पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन को पकड़ा था। जिसमें उन्हें किसी जंगली जानवर का 30 किलो मांस मिला। वाहन में सवार जौहर हुसैन पिता इब्राहिम निवासी मिल्लत नगर, मुंबई,सलमान पिता हारुन निवासी मोमिन नगर, मुंबई और इम्तियाज पिता शकरी खान निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई को गिरफ्तार किया। किशनगंज पुलिस ने मामला वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग की टीम पूछताछ के लिए आरोपियों को अपने साथ ले गई। आरोपी मांस को मुंबई ले जा रहे थे, लेकिन वे यह नहीं बता रहे है कि उन्होंने किस जंगली जानवर का शिकार किया। उनके वाहन से हथियार भी नहीं मिले। अफसरों को आशंका है कि ये लोग मांस के तस्कर है। स्थानीय लोगों ने शिकार कर मांस उन्हें बेच दिया। कहा जा रहा है कि जब्त मांस काले हिरन का है। सतवास और देवास के जंगलों में काले हिरण पाए जाते है। संभवत: वही से शिकार कर मांस लाया गया है। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि मीट वन्य प्राणी का है, लेकिन यह रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किस जानवर का है। हमने सैंपल जांच के लिए भेज दिए है।

13 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में तस्लीम चूड़ीवाला बरी

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर में तीन साल पहले हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने तस्लीम चूड़ीवाले को बरी कर दिया है। इस मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तस्लीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और एडवोकेट शेख अलीम के मुताबिक 2021 में यूपी के रहने वाला तस्लीम इंदौर में चूड़ियां बेचने के दौरान भीड़ का शिकार हुआ था। उसके आधार पर केस दर्ज किया गया था। उसे काफी समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। तस्लीम के खिलाफ 13 साल की नाबालिग लड़की की ओर से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में पीड़ित ने आरोपी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने इस सवाल से भी इनकार कर दिया कि आरोपी उसके पास चूड़ी बेचना आया था। तस्लीम पर दो आधारकार्ड रख गुमराह करने और अपनी पहचान छिपाने के भी आरोप लगे थे, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हुआ कि उसने छल करने के मकसद से आधारकार्ड की कूटरचना की है। कोर्ट के फैसले पर तस्लीम ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। वह इस घटना को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है। धर्म के आधार पर इस तरह का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए और हमारे देश में आपसी भाईचारा और गंगा-जमुनी तहजीब कायम रहनी चाहिए।

ठंडी पड़ी पार्किंग और सड़कों को कब्जों से मुक्त करने की मुहिम

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर में दीपावली के पहले शहर में नगर निगम द्वारा छेड़ी गई बिल्डिंगों में पार्किंग स्थलों से अतिक्रमण हटाने और सड़कों को कब्जों से मुक्त करने की मुहिम ठंडी पड़ गई है। सड़कों पर फिर अतिक्रमण है और बिल्डिंगों के बाहर सड़कों पर वाहनों की पार्किंग हो रही है। शहर में जहां पार्किंग की सबसे ज्यादा परेशानी है, वहां नगर निगम ने सिर्फ नोटिस थमाए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इंदौर में तीन माह पहले बड़े जोर शोर से शहर की 100 से ज्यादा बिल्डिंगों को सील किया गया था,क्योंकि उन बिल्डिंगों में पार्किंग के स्थान दफ्तर और दुकानें संचालित हो रही थी। निगम ने उन्हें तोड़ने के बजाए सील कर दिया। उनमें से कई स्थानों पर फिर वही गतिविधियां शुरू हो गई है। इसकी शिकायतें भी अफसरों तक पहुंची है।
इसके चलते अब फिर से उन बिल्डिंगों की जांच की जाएगी। उधर शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानों से कब्जे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान बनाने की मुहिम भी शुरू हुई थी, लेकिन दीपावली के पहले सपना संगीता क्षेत्र के व्यापारियों ने विरोध किया था और कहा था कि त्यौहार के समय इस तरह की मुहिम नगर निगम चला कर व्यापारियों का नुकसान कर रहा है। इसके बाद निगम की मुहिम ठंडी पड़ गई। तब मोबाइल कोर्ट चलाने की तैयारी भी की गई थी। इसके लिए विशेष वाहन भी तैयार किया गया, लेकिन वह भी संचालित नहीं हो पा रहा है। इंदौर के व्यस्त मार्केट जेलरोड पर 30 से ज्यादा बिल्डिंगों में छोटी-छोटी दुकानें संचालित होती है। यहां तलघर में पार्किंग की जगह है, लेकिन वहां भी दुकानें चल रही है। इस मार्केट की कुछ बिल्डिंगों में दुकानें सील हुई, लेकिन अभी भी पार्किंग सड़कों पर हो रही है।

महिला कारोबारी के साथ ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस

सिटी चीफ इंदौर।
महिला कारोबारी और उद्योगपति की बहू से ठगी मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया है। जिन अकाउंट में रुपए जमा हुए थे। उनकी भी जानकारी निकाल ली गई है। क्राइम ब्रांच की साइबर टीम इस मामले में जांच कर रही है। महिला कारोबारी ने पिछले सप्ताह राज्य साइबर सेल में जाकर अपने साथ 1 करोड़ 60 लाख की ठगी की शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि आरबीआई के अफसर ने उन्हें कॉल कर जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से परिचय होने की बात पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए धमकाया था। क्राइम ब्रांच ने वंदना गुप्ता की शिकायत पर अज्ञात फर्जी आरबीआई अफसर और सीबीआई अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वंदना गुप्ता को ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर कॉल किया था। पहला कॉल आरबीआई अफसर बनकर विनय सिंह ने किया। दिल्ली स्थित केनरा बैंक में अकाउंट में रुपयों के हेरफेर की बात कही। वीडियो कॉल पर बात करते हुए पुलिस अफसर की वर्दी पहने एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का बड़ा अफसर बताया। सीबीआई अफसर आकाश कुल्हाड़ी ने स्काय एप डाउन लोड करने के लिए कहा। कैमरा बंद नहीं करने करने की हिदायत दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी दी।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार बोले- भारतीय ज्ञान परंपरा कोर्स में होगी शामिल

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। मप्र के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार मंगलवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने रेसीडेंसी कोठी पर मीडिया से चर्चा की । मंत्री परमार ने कहा कि देश ने बहुत बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हो रहा है। भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया। उन सब चीजों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट और केंद्रीय अध्ययन दल पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में बात होती है तो पहली बार आजादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है, वह भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा भारत का दर्शन होगा भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो पहले आयोग बना था उस समय जो सिफारिश की थी पिछली सरकारों ने लागू नहीं किया।

भारतीय ग्रंथो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मंत्री परमार ने कहा कि जहां तक सवाल रहा शिक्षा नीति का, शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने के पक्ष में है। भारतीय परम्पराओं में भारतीय ग्रंथो में जहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और जो भारतीय परंपरा में निरंतर का प्रयोग करते हैं मैं समझता हूं उस विज्ञान को फिर से सामने लाना चाहिए, ताकि लोग प्रकृति है संस्कृति की रक्षा कर सकें।

निजी कॉलेजों के लिए कमेटी बनाई
मंत्री परमार ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम है। प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कोई शिकायत आती है तो आयोग उस पर संज्ञान लेता है। स्टूडेंट्स के लिए एक फोन नंबर जारी किया गया है। अगर कोई निर्धारित फीस से ज्यादा फीस मांगे तो शिकायत करें। उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस में बदलाव कर दिया है। अब सेमेस्टर प्रणाली ही रहेगी। क्योंकि सतत मूल्यांकन का आधार सेमेस्टर प्रणाली होती है। एक परीक्षा के माध्यम से किसी बच्चे के भाग्य का फैसला नहीं किया जा सकता।

बांग्लादेश की सरकार के प्रति आक्रोश
मंत्री परमार ने कहा की जो धार्मिक नेता है धार्मिक संत महात्मा है उनका अपना दर्शन है। जो दुनिया में घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भी आज एकत्रित हो रहे हैं। विशेष कर बांग्लादेश के संदर्भ में। जहां भारतीय सभ्यता है विरासत है। जिस प्रकार से हमले हो रहे है, आक्रमण हो रहे है इससे स्वाभाविक है की भारत का संत समाज उससे चिंतित है। उन्होंने बांग्लादेश की घटना को लेकर कहा की मध्यप्रदेश और देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है।
आक्रोश इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया। आज वहां के हिन्दू और सनातनीयों पर अत्याचार हो रहा है। मैं समझता हूं वहां की सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है।

40 साल पहले की वो काली रात... मोहन यादव भी थे भोपाल में मौजूद

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी में चार दशक पहले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि हादसे की रात वे भी भोपाल में थे और अगले दिन हादसे की भयावहता को देखा भी था। भोपाल गैस त्रादसी की 40वीं बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे इस तरह के प्रयास हैं कि आगे ऐसी दुर्घटना दोबारा न घटे। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ था, उस स्थान को लेकर भी सरकार गंभीर और ठोस पहल कर रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वे खुद इस पूरे घटनाक्रम के गवाह रहे हैं। उन्होंने इस हादसे की भयावहता को भी देखा है। हादसे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इस हादसे को हुए 40 साल हो गए हैं, जिस रात को यह हादसा हुआ था, उस समय मैं राजधानी के एमएलए रेस्ट हाउस में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आया था। इस बैठक में परिषद के कई पदाधिकारी आए थे और वे एमएलए रेस्ट हाउस में ही ठहरे थे। हादसे के अगले दिन उस स्थान पर भी गए थे, जहां गैस रिसाव का प्रभाव आया था। यह ऐसी त्रासदी थी जो जीवन में कभी पहले देखी ही नहीं थी, जैसी भोपाल और दुनिया ने यह त्रासदी देखी थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विजय शाह, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, भोपाल महापौर मालती राय, भोपाल की दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल पूरे होने पर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने गैस से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। डॉ. यादव ने अपनी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर भी दी, जहां उन्होंने इस त्रासदी में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से अब तक सरकार और अन्य संगठनों द्वारा प्रभावितों की सहायता के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस दर्दनाक घटना के जख्म आज भी लोगों के दिलों में ताजे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस त्रासदी में असमय अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह प्रभावित नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाए।

गैस त्रासदी की बरसी पर हुई सर्वधर्म सभा
भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर मंगलवार को भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया तथा बुजुर्ग गैस पीड़ितों को सम्मानित किया गया। साथ ही बीएमएचआरसी के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर डाक विभाग द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया गया। बीएमएचआरसी में सुबह साढ़े 8 बजे श्रद्धांजलि एवं आशा स्मारक के पास शुरू हुई सर्वधर्म सभा में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने-अपने धर्मग्रंथों का पाठ किया। इसके बाद 85 वर्ष अधिक उम्र के गैस पीड़ित बुजुर्ग मरीजों का सम्मान किया गया।

स्वास्थ्य शिविर लगाए गए
मप्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बीएमएचआरसी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, निशुल्क जांच एवं दवा वितरण, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। शिविरों में आभा तथा आयुष्मान आईडी बनाई जा रही है। रोटरी क्लब एवं महावीर इंटरनैशनल नामक संस्थाओं द्वारा गरीब मरीजों के लिए कंबल भी दान किए गए हैं, जिन्हें वार्डों में वितरित किया जाएगा।

डाक विभाग ने विशेष आवरण जारी किया
बीएमएचआरसी ने हाल ही में अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर संस्थान के इस योगदान को चिन्हित करने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया गया। डाक विभाग द्वारा जारी किया गया विशेष आवरण एक विशिष्ट डाक कवर होता है, जो किसी महत्वपूर्ण अवसर, घटना, व्यक्ति, स्थान, या किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या वैज्ञानिक महत्व के विषय को समर्पित होता है। विशिष्ट विषयों पर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भी इसे जारी किया जाता है। इसे खास डिजाइन और प्रतीकों के साथ तैयार किया जाता है, जो उस अवसर या विषय का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मौके पर मप्र सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सुनीत माथुर, डाक सेवाओं के प्रमुख पवन कुमार डालमिया एवं बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव मौजूद रहीं।

शहीद हुए रेल कर्मियों को भी किया याद
गैस त्रासदी में शहीद हुए रेल कर्मियों की स्मृति में भोपाल स्टेशन पर स्थापित शहीद स्मारक पर मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी समेत रेलवे अधिकारी-कर्मचारियों ने गैस त्रासदी में शहीद हुए रेल कर्मियों को श्रद्धांजलि दी।

आने वाली पीढ़ी की इसकी चपेट में
भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से दो-तीन दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।
इस रात हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे और बड़ी संख्या पर इस जहरीली गैस ने अपना प्रभाव छोड़ा था। यह संयंत्र तो हादसे के बाद से बंद है। मगर इसका दुष्प्रभाव अब भी लोगों की जिंदगी पर है। गैस की जद में आए लोग तो बीमारियों की गिरफ्त में हैं ही, साथ में जन्म ले रही पीढ़ी भी इससे बच नहीं पा रही है।
इस हादसे की याद में राजधानी में 3 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हादसे का शिकार बने लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है।

फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

6 कॉल सेंटर चलाकर ठगा जा रहा था कुंवारों को, गिरोह का मैनेजर गिरफ्तार

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। पुलिस ने भोपाल में ऑनलाइन शादी के झांसे में फंसाने वाले गिरोह का पदार्फाश किया है। इस गिरोह का मैनेजर हरीश भारद्वाज, जो मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है और फिलहाल बिलासपुर में रहता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह छत्तीसगढ़ से 6 फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट और 6 कॉल सेंटर चलाकर कुंवारों को ठगता था। ये लोग सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को अपनी वेबसाइट पर आकर्षित करते थे, फिर फर्जी प्रोफाइल दिखाकर रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य खर्चों के नाम पर पैसे ऐंठ लेते थे। मई में इसी गिरोह ने भोपाल के एक युवक से डेढ़ लाख रुपए ठगे थे। आरोपी हरीश भारद्वाज जब अपने सीज बैंक खाते खुलवाने भोपाल आया, तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस का अनुमान है कि यह गिरोह 500 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। हरीश भारद्वाज इस गिरोह में मैनेजर की भूमिका निभा रहा था और केवल 12वीं पास है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि गिरोह ने अब तक 500 से अधिक लोगों को ठगा है।

फर्जी मैट्रिमोनियल साइट का देता था विज्ञापन
यह गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को ठगता था।
सबसे पहले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट का विज्ञापन देते थे। इन वेबसाइट के नाम इंडियन रॉयल मैट्रिमोनी, सर्च रिश्ते, ड्रीम पार्टनर इंडिया, 7 फेरे मैट्रिमोनी, संगम विवाह, और माय शादी प्लानर थे। विज्ञापन में लड़कियों की इंटरनेट से डाउनलोड की गई तस्वीरें और फर्जी बायोडाटा इस्तेमाल किए जाते थे। जब कोई व्यक्ति विज्ञापन पर क्लिक करता था, तो वह सीधे उनके वाट्सएप

ग्रुप में जुड़ जाता था। वहां उन्हें और भी लड़कियों की तस्वीरें और बायोडाटा दिखाए जाते थे।

रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर करते थे वसूली
जैसे ही कोई व्यक्ति किसी प्रोफाइल में दिलचस्पी दिखाता था, गिरोह के सदस्य उससे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगते थे। रजिस्ट्रेशन के बाद, पीड़ित को एक फोन नंबर दिया जाता था, जो उनके कॉल सेंटर में काम करने वाली किसी लड़की का होता था। यह लड़की फिर शादी की तैयारियों, शॉपिंग, दस्तावेज तैयार करने जैसे बहाने बनाकर पीड़ित से और पैसे ऐंठती रहती थी।

मई में भोपाल के युवक ने दर्ज कराई शिकायत
भोपाल के कस्तूरबा नगर निवासी आनंद कुमार दीक्षित भी इस गिरोह का शिकार बन गए थे। मई में उन्होंने फेसबुक पर ह्यसंगम विवाह मैट्रिमोनी का विज्ञापन देखा और संपर्क किया। कॉल सेंटर की लड़कियों ने उनसे अलग-अलग खर्चों के नाम पर कुल डेढ़ लाख रुपये ले लिए। आनंद कुमार ने 4 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पोर्टल पर भी शिकायत की।

अकाउंट अनफ्रिज कराने आया था भोपाल
भोपाल क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के बैंक खाते सीज कर दिए थे। हरीश भारद्वाज इन्हीं खातों को फिर से चालू करवाने के लिए भोपाल आया था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सदस्य जानबूझकर छोटी-छोटी रकम ठगते थे ताकि लोग पुलिस में शिकायत न करें। अगर कोई ज्यादा परेशान करता था, तो वे किश्तों में पैसे वापस भी कर देते थे। कभी-कभी तो वे खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों को धमकाते भी थे। पुलिस अब हरीश भारद्वाज से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है।

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ सोमवार को बैठक की है। इसमें सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन पर चर्चा की गई है। मुख्य सचिव ने इसके लिए परिवहन विभाग को जल्द नीति तैयार करने को कहा है, ताकि आने वाले दिनों में इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा कर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सके। मुख्यमंत्री, लोक परिवहन को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रारंभ करने की इच्छा जता चुके हैं। इसके बाद इस दिशा में नए सिरे से कवायद शुरू हुई है और मुख्य सचिव जैन ने इसको लेकर नीति बनाने पर फोकस किया है। प्रदेश में 2005 में सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद से प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सेवा नहीं है। स्थानीय स्तर पर नगरीय निकायों द्वारा कंपनी बनाकर कुछ बसों का संचालन किया जाता है। अब सार्वजनिक परिवहन में ग्रामीण इलाकों को परिवहन की बेहतर सुविधा देने के हिसाब से काम किया जाना है। इसके लिए ग्रामीण परिवहन की परिस्थितियों को फोकस कर काम करने को कहा गया है। इस काम में अर्बन निकायों की भी भागीदारी पर चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण परिवहन को लेकर नीति बनाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने गांवों से बस सेवा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी की शिकार है। इसे भी ठीक करने पर नए नियमों में विचार किया जाएगा। आज हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा समेत परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

धमकी मिलने के बाद पं. धीरेंद्र शास्त्री बोले-हम नहीं चाहते हिन्दू-सिख अलग हो

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब के खन्ना राजपुरा के रहने वाले कट्टपंथी बलजिंदर सिंह परवाना ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने हरिमंदिर साहिब के बारे में गलत शब्द कहे हैं। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अब इस मामले में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर अपना जवाब दिया है। दरअसल, पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने लगाए गए दरबार में कहा था कि हरिहर मंदिर में भी पूजा होनी चाहिए। मंदिर में अभिषेक और रुद्राभिषेक होना चाहिए। हालांकि उनका बयान विवादित नहीं था। क्योंकि पं. धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में हरिहर मंदिर का जिक्र किया था। दरअसल बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने यह बयान अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) के लिए नहीं दिया है। उन्होंने कलकी धाम संभल (यूपी) का जिक्र किया है। संभल में हरि का हर मंदिर है। मामले को तूल पकड़ता देख बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के परवाना जी ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सरदार हमारे मित्र हैं...हमारे भाई हैं। हमें उनकी तालियां भी स्वीकार और उनकी गलियां भी स्वीकार है। हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख अलग-अलग हो जाएं। हरमिंदर साहिब के प्रति हमारी निष्ठा है। सिख गुरुओं के प्रति हमारी अपार श्रद्धा है। हम सपने में भी इस तरह का विचार नहीं ला सकते।

बड़े तालाब स्थित बोट क्लब में डूबने से युवक की मौत

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार रात की है। युवक के बड़े भाई ने बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ बड़े तालाब पर गया था। रात 10 बजे उसकी दोस्त ने कॉल पर घटना की जानकारी दी। भाई ने मौके पर पहुंच कर पुलिस को सूचना दी। रात 10.30 बजे गोताखोर ने युवक का शव तालाब से निकाला और हमीदिया स्थित मॉचुर्री में भेजा। बड़े भाई के मुताबिक, घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है।
पोस्टमॉर्टम और भाई की दोस्त के बयान से ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। आशंका है कि दोनों के बीच विवाद हुआ था। जिस वजह से आत्महत्या का शक है। वहीं, मंगलवार को श्यामला हील्स थाना पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर युवक का शव का परिजनों को सौंप दिया है।
बड़े भाई योगेश यादव ने बताया कि वंश यादव (19) पिता नर्मदा प्रसाद यादव, निवासी ओल्ड विधानसभा भवन के पास न्यू मार्केट स्थित एक दुकान पर काम करता है। वंश का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध है। दोनों के घर वालों को इसकी जानकारी है और कोई भी विरोध नहीं है। दोनों की शादी करवाने की बात भी चल रही है। उसी लड़की के साथ वो बोट क्लब गया था। वंश के पिता गार्ड का काम करते हैं। वंश तीन भाइयों में मंझला था। उसके दोनों भाई भी न्यू मार्केट में दुकानों पर काम करते हैं। घटना के बाद से मां का रो-रोकर बुरा हाल हैं। वहीं परिजनों में शोक की लहर है।

नगर निगम ने लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए बनाया अनोखा प्लान

भोपाल। भोपाल में एक ऐसा प्रयोग हो रहा है, जिसमें लोग बस में बैठकर ही बसों का इंतजार करेंगे। जल्द ही इस बस को स्टॉप पर रखा जाएगा। अब निगम ने इससे आगे एक कदम और बढ़ाया है। कंडम लो फ्लोर बस में रैन बसेरे भी बनाए जाने का प्लान है, ताकि कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाया जा सके। भोपाल में नवंबर में ही तेज ठंड का असर शुरू हो गया था। दिसंबर के शुरूआती दो दिन भी ठंडे रहे। रविवार-सोमवार की रात पारा 8.5 डिग्री पर पहुंच गया, जो पिछले साल से भी कम है। आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए निगम कंडम बसों को रैन बसेरे के रूप में बदलने का प्लान तैयार कर रहा है। शाहजहांनी पार्क, बैरागढ़ समेत कई इलाकों में रैन बसेरे हैं, जहां ठंड में रुकने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई है। हाल ही में बैरागढ़ में एक और रैन बसेरे के लिए एमआईसी मेंबर राजेश हिंगोरानी ने मांग की थी। ऐसे में निगम कंडम बसों को रैन बसेरे के विकल्प के रूप में देख रहा है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ महाकुंभ कॉन्क्लेव 19वां गोलमेज सत्र

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में इंडिया थिंक काउंसिल द्वारा महाकुंभ कॉन्क्लेव 19वां गोलमेज सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. रमाकान्त पाण्डेय (निदेशक भोपाल परिसर) ने की, उन्होंने महाकुंभ के वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक के महत्व पर चर्चा की। प्रो. पाण्डेय ने कहा, महाकुंभ न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। उन्होंने महाभारत और ऋग्वेद के संदर्भ में महाकुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर किया।

ऋषि-महर्षियों का अद्भुत संगम है कुंभ
मुख्य वक्ता धनंजय चोपड़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कुंभ को अलौकिक और अद्वितीय बताया। उन्होंने इसे जन संस्कृति का मेला और ऋषि महर्षियों के अद्भुत संगम के रूप में परिभाषित किया। चौपड़ा ने रामचरित मानस की चौपाई उद्धृत करते हुए महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया और इसे भारतीय चेतना के प्रसार का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. अमिताभ पाण्डेय ने महाकुंभ को जीवन संस्कृति का उदाहरण बताते हुए कहा कि कुंभ एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां आस्था और विश्वास का संगम होता है। उन्होंने महाकुंभ में निरंतरता, वैयक्तिक विविधता और सांस्कृतिक चेतना पर विचार करने की आवश्यकता जताई।

हरित महाकुंभ की आवश्यकता
सत्र के दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रो. हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रो. नीलाभ तिवारी ने भी महाकुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। प्रो. तिवारी ने महाकुंभ के पर्यावरणीय पहलुओं पर बल देते हुए हरित महाकुंभ की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस कार्यक्रम का संचालन प्रो. कृपाशंकर शर्मा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रो. भारत भूषण मिश्र ने महाकुंभ के ज्योतिषीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए किया। कार्यक्रम के मुख्य प्रस्तावक सौरभ पाण्डेय थे । इस सत्र में परिसर के सभी प्राध्यापक, शोध छात्र और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर कल्याण मंत्र के साथ इस विचार-मंच का समापन हुआ, जो महाकुंभ के सशक्त आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान को सम्मानित करता है।

सम्पादकीय

जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर डाल रही दबाव

देश की जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डाल रही है, जिससे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, और गरीबी और असमानता बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक चुनौती बन जाती है। शिक्षा का बुनियादी ढांचा बढ़ती आबादी की जरूरतों से जूझ रहा है, और शहरीकरण के कारण मूलभूत आवश्यकताओं और आधारभूत अवसंरचना पर दबाव बढ़ गया है। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती आबादी के बोझ ने पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ावा दिया है।

देश में विभिन्न दलों के राजनेता और धार्मिक नेता अपने लक्षित समूहों की आबादी बढ़ाने की जरूरत बताते रहे हैं। आबादी के बोझ से चरमराती नागरिक सेवाओं और सीमित संसाधनों के बीच आबादी बढ़ाने का आह्वान करना तार्किक दृष्टि से गले नहीं उतरता। लेकिन इसके बावजूद धार्मिक व सांप्रदायिक समूह के अगुआ आबादी बढ़ाने का आह्वान करते नजर आते हैं। इस मुद्दे की हालिया चर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी के कारण फिर सुर्खियों में है। उनका कहना है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। उन्होंने एक तस्वीर उकेरते हुए कहा है कि जिस समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाएगी, कालांतर उस समाज को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी दलील है कि बहुसंख्यक समाज को हम दो, हमारे तीन के समाधान पर अमल करना चाहिए। यानी प्रत्येक जोड़े को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने एक समुदाय विशेष को इंगित करते हुए चिंता जताई थी कि अधिक आबादी वाला समुदाय जनसंख्या संतुलन के लिए चुनौती पेश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस भाषण के कुछ सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के निष्कर्ष में इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक समाज की आबादी में 7.82 फीसदी की कमी आई है। वहीं देश के मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में 43 फीसदी की वृद्धि हुई है। दरअसल, इन्हीं आंकड़ों के जरिये भविष्य में बहुसंख्यक समाज के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के रूप में पेश किया जाता है। दरअसल, राजनीतिक नेतृत्व व धार्मिक संगठनों के नेताओं द्वारा जनसंख्या नीति को लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं, वे एक अर्थशास्त्री द्वारा लक्षित जनसंख्या की संकल्पना दृष्टि के मद्देनजर विरोधाभासी कही जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने में छोटे परिवार मददगार साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से जनसंख्या से जुड़ी विरोधाभासी दलीलों की तार्किकता तलाश पाना एक कठिन कार्य रहा है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि देश में परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक के प्रयोग में वृद्धि के कारण प्रजनन दर में काफी गिरावट आई है। वहीं ऐसे ही तात्कालिक कारणों तथा राजनीतिक लक्ष्यों ने आंध्रप्रदेश में टीडीपी सरकार को दो संतानों की नीति को खत्म करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी ही जनसंख्या नीति में बदलाव के लिये तमिलनाडु सरकार की तरफ से विरोधाभासी बयान विगत दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बने हैं। ऐसे हालात में विभिन्न राज्यों में सरकारों को चाहिए कि वे जनसंख्या नीति पर बयानबाजी करने से पहले उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करें। वे विचार करें कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की चुनौती के बीच क्या वे अतिरिक्त जनसंख्या के बोझ को संभाल पाने में सक्षम हो सकते हैं? हमारी प्राथमिकता हर हाथ को काम देने तथा सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग होनी चाहिए। यदि ऐसे हालात में आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो कालांतर जनसंख्या के दबाव से चरमराती नागरिक सेवाओं के ध्वस्त होने की आशंका बलवती हो जाएगी। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और वह अपनी तेजी से बढ़ती आबादी के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

गरीब कैदियों को जमानत नहीं मिल पाना भी अन्याय

जमानत पर रिहा न हो सकने वाले कैदियों की लंबी हिरासत का उन पर और उनके परिवार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उनके परिवार मुख्य कमाने वाले को खो देते हैं और वे गरीबी में और गहरे धंस जाते हैं। बच्चों को अकसर स्कूल छोड़ना पड़ता है। जबकि परिवार जेल में बंद अपने प्रियजनों के कारण कलंक और अलगाव झेलते हैं। ऐसे गरीब बंदियों के परिवार का विभिन्न तरीके से शोषण के मामले भी प्रकाश में आए हैं। भीड़भाड़ वाली, अमानवीय परिस्थितियों में रहना और भविष्य की अनिश्चितता उनकी गरिमा और न्यायिक प्रणाली में विश्वास को नष्ट कर देती है।

न्याय किसी भी शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है और समानता उस न्याय व्यवस्था का एक मौलिक आधार है। अगर न्यायिक व्यवस्था में अमीर-गरीब के भेद की गुजांइश हो तो वह व्यवस्था न केवल अपूर्ण होती है बल्कि न्याय के बजाय अन्याय को भी जन्म देती है जिसका परिणाम असंतोष और अराजकता के रूप में सामने आ सकता है। विख्यात फिल्म अभिनेता सलमान खान को 7 अप्रैल 2018 को जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से जमानत मंजूर होने पर मात्र कुछ ही घंटों में जेल से रिहा कर दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (सीआरपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार- दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्टों द्वारा जमानत मंजूर होने के बावजूद 24,879 गरीब आरोपी जेलों में बंद थे, क्योंकि वे जमानत बॉण्ड पेश नहीं कर सके। यही नहीं देश की जेलों में हजारों की संख्या में विचाराधीन कैदी बिना सजा सुनाए 5 साल से अधिक समय से सजा भुगत रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट 2019 के एक फैसले में कह चुका है कि जमानत राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में कैदियों को जेल में रखना अवैध और कैदी के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति अभय ओका और एजी मसीह की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जमानत राशि अदा न कर सकने वाले कैदियों को रिहा न किए जाने पर इसी महीने हैरानी जताई है। इससे पहले भी सर्वोच्च अदालत 2023 और 2021 में इस मुद्दे पर चिंता जताने के साथ ही सरकार को गरीब कैदियों की जमानत पर रिहाई की व्यवस्था करने का निर्देश दे चुकी थी, जिसके अनुपालन में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में गरीब कैदियों के लिए जमानत पर रिहा होने के लिये वित्तीय सहायता का प्रावधान किया था।

इस योजना में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के आधार पर विचाराधीन कैदियों के लिए 40,000 रुपए और दोषियों के लिए 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। योजना को लागू करने के लिए 23 मई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्य मंत्रियों को और फिर 23 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्रालय के उपसचिव अरुण सोब्ती ने सभी राज्यों के गृह सचिवों और पुलिस प्रमुखों को पत्र लिख कर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा था। लेकिन बावजूद इन प्रयासों के अदालत से जमानत मिलने पर भी बड़ी संख्या में गरीब कैदियों का जेल से न छूट पाना हमारी अपराधिक न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ही है।

भारत की न्याय प्रणाली निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। मगर व्यवहार में यह प्रणाली उन लोगों को प्राथमिकता देती है जिनके पास धन और प्रभाव है, जिससे वे कानूनी राहत को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक जेलों में पड़े रहते हैं। न्याय भी अक्सर महंगे और सस्ते तथा सुलभ वकीलों पर निर्भर करता है, इसलिए समाज में कई अहंकारी आज भी न्याय खरीदने का दंभ भरते हें।

देखा जाए तो जमानत का उद्देश्य अभियुक्त के अधिकारों और अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि न्याय का सिद्धान्त तब तक किसी आरोपी को निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। सन् 2023 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत की जेलों में 5,73,000 से अधिक कैदियों में 75 प्रतिशत से अधिक ऐसे विचाराधीन हैं जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम जेल सांख्यकी के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारतीय जेलों में कुल 4,27,165 विचाराधीन कैदी थे जिनमें से 11,490 कैदी अदालत से जमानत मिलने पर भी जेलों में निरुद्ध थे। इन विचाराधीन बंदियों में 382 महलाएं भी थीं। इन विचाराधीन बंदियों में 1,07,946 अनपढ़ कैदी थे जिन्हें अपने अधिकारों और न्यायिक प्रकृया का ज्ञान ही नहीं था। न्याय पर रुतबे और धन का जीता जागता उदाहरण फिल्म अभिनेता सलमान खान का 2018 का मामला है।

जमानत पर रिहा न हो सकने वाले कैदियों की लंबी हिरासत का उन पर और उनके परिवार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उनके परिवार मुख्य कमाने वाले को खो देते हैं और वे गरीबी में और गहरे धंस जाते हैं। बच्चों को अकसर स्कूल छोड़ना पड़ता है। जबकि परिवार जेल में बंद अपने प्रियजनों के कारण कलंक और अलगाव झेलते हैं। ऐसे गरीब बंदियों के परिवार का विभिन्न तरीके से शोषण के मामले भी प्रकाश में आए हैं। भीड़भाड़ वाली, अमानवीय परिस्थितियों में रहना और भविष्य की अनिश्चितता उनकी गरिमा और न्यायिक प्रणाली में विश्वास को नष्ट कर देती है। बरी होने पर उनका जीवन आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से अक्सर बहुत प्रभावित हो चुका होता है। जेलें बीमारियों का घर होती हैं। कई विचाराधीन कैदी लम्बे समय बाद जेल से छूट तो जाते हैं लेकिन वे घर पहुंचते हैं तो उनके साथ असाध्य रोग भी होते हैं।

गरीब कैदियों की लंबे समय तक हिरासत को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन अपर्याप्त है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436ए उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई को अनिवार्य करती है, जिन्होंने उनके आरोपित अपराध की अधिकतम सजा का आधा समय जेल में बिताया जा चुका है। इसी प्रकार, 2005 में मामलों को तेजी से निपटाने और अदालतों पर बोझ कम करने के लिए दोष-स्वीकृति को पेश किया गया था। हालांकि, इन प्रावधानों का उपयोग बहुत कम होता है। जमानत के लिए आर्थिक स्थितियों पर विचार किए बिना केवल वित्तीय जमानत पर निर्भर रहना दंडात्मक प्रणाली को बढ़ावा देता है।

गरीबों के लिए कानूनी सहायता सेवाएं, जो उनकी मदद करने के लिए बनाई गई हैं, अक्सर संसाधनों की कमी से जूझती हैं और व्यक्तिगत बांड या सामुदायिक गारंटी जैसे विकल्पों की वकालत करने में विफल रहती हैं।

भारत की न्याय प्रणाली एक चौराहे पर है। गरीब कैदियों की लगातार कैद, कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं के बावजूद, संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में बदलने में विफलता को दर्शाती है। आर्थिक स्थिति को आजादी तक पहुंच के लिए बाधा नहीं बनने देना न्यायपालिका में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है। गरीब कैदियों की दुर्दशा समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं की याद दिलाती है। यह नीति-निर्माताओं, कानूनी पेशेवरों और नागरिक समाज के लिए एकजुट होकर एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत प्रणाली बनाने का आह्वान है। सच्चा न्याय तभी संभव है जब हर व्यक्ति, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अपने अधिकारों तक समान पहुंच रखे।

सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करिए

हम भाजपाई हो सकते हैं या कांग्रेसी, या समाजवादी या बहुजनवादी। वाम हो सकते हैं या दक्षिण, किन्तु अंत में हम सब भारतीय हैं, और भारत की सुरक्षा, समृद्धि और आपसी सद्भाव से ही हमारा भविष्य जुड़ा है। हम कुछ भी होकर सोचें, भारत के भविष्य से हमारा भविष्य अलग नहीं हो सकता। हमें विकास चाहिए तो उसको भोगने के लिए शांतिपूर्ण माहौल भी चाहिए, जो आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार से वांछित है। एक देश के अंदर हम समुदायों, संप्रदायों की भिन्नता के कारण उलझते रहें या देशों के आपसी विवादों के कारण, अंत में आम आदमी को ही इन विवादों का शिकार होना है। अधिकांश विवाद प्रभुत्व की भूख के चलते ही होते हैं। फिर चाहे बहाना आप सांप्रदायिक बना लें या आर्थिक, विस्तारवादी बना लें, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का बना लें, निचोड़ तो प्रभुत्व की भूख ही है। प्रभुत्व के बजाय समानता को लक्ष्य बना लें तो अपने आप निष्कर्ष ऐसे आने लगेंगे जिनमें टकराव की जरूरतें ही कम होती जाएंगी। यह विश्लेषण जितना भारत के लिए प्रसंगिक है, उतना ही वैश्विक पटल के लिए भी है। फिलहाल बात तो भारत की कर लें। आजकल बड़ी दुविधाजनक स्थिति में से हम गुजर रहे हैं। विकास की दौड़ में हमें अच्छी सफलताएं मिल रही हैं तो हम सभी मिल कर उसका फल उपभोग करें, यह सर्वमान्य लक्ष्य होना चाहिए, किन्तु सरकार के यह बार-बार कहने के बाद भी उसी सरकार का दूसरा चेहरा हिन्दू-मुसलमान में उलझा रहता है। राजनीतिक दलों की ऊपरी परत कुछ और कहती है और नीचे की परतें कुछ और कहती नजर आती हैं। पत्रकारिता अर्धसत्य अनुगामी होती जा रही है और उसे नियंत्रित करने के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास सामने दिखने लग जाते हैं। टीवी पर जिस तरह की बहसें मुद्दों को लेकर दिखाई जाती हैं, उनसे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि ये आपसी भेदभाव, खासकर हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही हैं। उनमें जिस तरह के लोगों को ज्यादातर बुलाया जाता है उनमें से नगण्य ही समाधानमुखी दृष्टिकोण लेकर बैठते हैं। चाहे हिन्दू जानकार हों या मुस्लिम, सभी ढूंढ ढूंढ कर विवाद बढ़ाने वाली बातों को उछालते दीखते हैं। अधिकांश चैनल ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आते हैं। मुसलमान नेतृत्व में छुपे तौर पर यह भावना काम करती दिखती है कि वे तो इस देश के हुक्मरान रहे हैं, इसलिए हमारा स्तर तो कुछ विशेष ही होना चाहिए। अभी तक भी उनमें से कई ह्यगजवा-ए-हिन्दह्ल जैसे अप्रासंगिक विचारों के अनुगामी दीखते हैं। और हिन्दू नेतृत्व इस हीनभावना से ग्रस्त दीखता है कि क्योंकि मुस्लिम आक्रान्ताओं ने हिन्दुओं के साथ अन्याय और अत्याचार किया, इसलिए अब हमारे हाथ में बागडोर आई है, तो हम उसका बदला अब पूरा करेंगे। ये दोनों ही विचार खतरनाक हैं। क्योंकि ये दोनों विचार हमें भूतकाल में जीने की ओर ले जाते हैं, जबकि असल जिन्दगी तो वर्तमान में चलती है। हमें तो अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना है। और यह संघर्ष सारे भारत वासियों का सांझा संघर्ष है।

जो हमें आपस में नहीं करना है, बल्कि वैश्विक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों से करना है, और इसकी उपलब्धियों के फल हम सभी को सांझा करने हैं। यह बात समझना कोई कठिन बात तो नहीं है, बल्कि इससे अलग दिशा की बात को समझने के लिए ज्यादा तिकड़म और बनावटी कहानियां गढ़ने और समझने की जरूरत होगी। देश में बीस करोड़ के लगभग मुस्लिम आबादी है, जिसे विकास का हिस्सेदार बनाए बिना देश का विकास संभव नहीं। विकास का हिस्सेदार बनाने का यह अर्थ नहीं कि वे अपनी शर्तों पर जो चाहे वह करने का प्रयास करें, और यह भी नहीं कि हिन्दू जो बहुमत में हैं, वे अपनी मनमानी सोच को लागू करने की दिशा में बढ़ने का सोचने लगें। हम सभी धर्मों-पंथों, भाषाओं, क्षेत्रों के लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए कोई विशेषाधिकार न मांगें, यही न्यायपूर्ण विकास का मार्ग है। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम आक्रान्ताओं ने हमारे हिन्दू मंदिरों को तोड़ा किन्तु उन घटनाओं को हम आज के वातावरण को खराब करने का कारण नहीं बना सकते। जहां भी विवाद की स्थिति आती है तो देश के कानून और न्याय व्यवस्था से मामले हल हों। राम मन्दिर विवाद में दोनों पक्षों ने आरंभिक दुराग्रहों के बावजूद अंत में न्याय व्यवस्था पर अनुकरणीय रूप से सद्भावना स्थापित करने में योगदान दिया। अब हर जगह नए नए विवाद ढूंढने के प्रयास न किए जाएं। हम मुसलमान या हिन्दू होकर सोचना बंद करें, बल्कि भारतीय होकर सोचें तो समाधान आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। क्या कारण है कि धार्मिक जलूसों पर पथराव किया जाए, या एक-दूसरे को चुभने वाली नारेबाजी की जाए। क्या इससे ईश्वर या खुदा खुश हो सकता है, कभी नहीं। ऐसे लोगों पर समय पर उचित कानूनी नियंत्रण होना चाहिए जो वोट राजनीति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगे रहते हैं। हालांकि सब एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, किन्तु समाज तो समझता है कि सभी कम या ज्यादा, समाज को जातियों या संप्रदायों में बांट कर फूट डाल कर उनके वकील बन कर वोट हासिल करने के चक्कर में ही रहते हैं। यदि आप सच में ही निष्पक्ष सेवा करेंगे तो सभी वर्गों के वोट आपको आपके काम के हिसाब से मिल सकते हैं। राजनेताओं में यह आत्मविश्वास होना चाहिए। हम अपने अपने धर्म को अच्छा मानें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किन्तु दूसरे के धर्म को गलत या छोटा साबित करना छोड़ दें तो सद्भाव कायम करना आसान होगा। आखिर हमारे ईश्वर को इस तरह या उस तरह मानने से सूरज-चांद अपना रास्ता तो नहीं बदल लेंगे। प्रकृति अपना काम बिना किसी भेदभाव के करती ही रहेगी। हमें ही सुख से जीने की अक्ल हासिल करने की जरूरत है। अपने लिए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। ईश्वर को पाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, यह मानना एक-दूसरे के धर्म का आदर करना सिखाने का आसान तरीका हो सकता है। हां! हमें प्रभुत्ववाद से समतावाद की ओर बढ़ना सीखना पड़ेगा, यही प्रजातंत्र का असली आधार है।

दिल्ली पर बार-बार क्यों चढ़ाई करते हैं किसान?

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रूक गए।

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया।

दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती है। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि है उनके पास।

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें जमीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवजा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंडियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे। प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बडा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हांलाकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से जूझते दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे, एमबूलेंस भी नहीं निकल पाईं। नौकरीपेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा।

धरना स्थल पर जनपद अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ सरपंचों का विरोध

प्रशासन ने कराया धरना समाप्त

सुनील यादव । सिटी चीफ
कटनी, कटनी के जनपद पंचायत के बाहर बिना अनुमति धरना दे रहीं जनपद अध्यक्ष गीता बाई एवं अन्य सदस्यों को जब जिला और पुलिस प्रशासन हटाने पहुंचा तो वह धरने से उठने से मना कर दिया इस दौरान बहसबाजी भी हुई इस बीच अचानक सरपंच भी मौके पर पहुंच गए और जनपद पंचयत अध्यक्ष के साथ धरने पर बैठे वी के पटेल और सदस्यों के साथ तीखी बहस बजी करते हुए उन्हें धरना स्थल से भागा दिया। सरपंचों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जनपद पंचायत की अध्यक्ष गीता बाई को बरगला कर जबरन धरने पर बैठने वाला वी के पटेल एवं अन्य सदस्य संरपंचों से अवैध वसूली करते है और काम न होने पर धरने पर बैठने धमकी देते है। और देखते ही देखते धरना स्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई हालांक की मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए धरने को समाप्त करवाया। इस दौरान मौके पर एसडीएम प्रदीप मिश्रा, तहसीलदार बी के मिश्रा ने धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए प्रदर्शन के लिए विधिवत अनुमति प्राप्त कर धरनास्थल पर ही अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कहा। विदित हो कि जनपद पंचायत कटनी के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनपद अध्यक्ष गीता बाई एवं सदस्यों और अन्य समर्थकों ने मोर्चा खोलये हुए दो दिनों से जनपद पंचायत के बाहर धरना दे रहे थे। कुछ दिन पहले कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग भी की गई थी लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर सोमवार से जनपद पंचायत की अध्यक्ष गीता बाई ने अपने कुछ सदस्यों और समर्थकों के साथ जनपद के बाहर धरना दे दिया था हालांकि धरना के लिए अनुमति भी मांगी गई थी लेकिन प्रशासन ने यह कहकर अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि तहसील परिसर में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। आज जब प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में धरना समाप्त कराने पहुंची तो उनके बीच बहस शुरू हो गई और वहीं मौके पर कुछ सरपंच भी पहुंच गए और धरने पर बैठे वी के पटेल पर अवैध वहसूली का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से उन्हें वहा से हटवा दिया।

जंग का मैदान बनी ड्रीम इंडिया स्कूल, अभिभावक हुए परेशान

टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह आपस में करते हैं हाथापाई

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ
सतना, जिले के भरहुत नगर स्थित ड्रीम इंडिया स्कूल इस समय जय जंग का अखाड़ा बन गई है। गुरू शिष्य का संबंध भक्तिपूर्ण होना चाहिए। शिष्य का संह कर्तव्य गुरू की और हमेशा रहना चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु की आदर समान भी करना सीखना चाहिए। और बात आई संबध की तो, एक अच्छे गुरु को शिष्य को सही मार्ग पे चलना सिखाना चाहिए और एक शिष्य को गुरु की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन इस स्कूल में इस के समय टीचरों का आपसी ताल मेल ना होने के कारण आये दिन आपस में मारपीट वा झगड़ा करने की बातें सुनने को मिल रही में है। जहां अभिभावक अपने बच्चों को एक त्रां मोटी रकम देकर स्कूल में शिक्षा के लिए 5, पढ़ने भेजता है, और उम्मीद करता है कि में हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा व बेहतर सुविधा मिले, और एक अच्छे सामाजिक वातावरण में हमारा बच्चा पले बढे, लेकिन गुरु शिष्य की गरिमा को तार-तार करते हुए सारी हदें पार कर दी गई है, आए दिन आपसी विवाद के कारण छोटे-छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, और बच्चों के बीच गलत मैसेज जा रहा है। जब स्कूल के अंदर टीचरों में ही डिसिप्लिन नहीं है, तो बच्चों को यह क्या डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाएंगे और सिखाएंगे यह बड़ा सवाल है...? वहीं कई पेरेंट्स इस आपसी खींचातानी के चक्कर में परेशान होकर चिंतित नजर आए, कई पेरेंट्स से बात करने पर पता चला कि पिछले कई महीनो से स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है, स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, वही बच्चों ने अपने पेरेंट्स से बताया की टीचर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और सभी बच्चों को बोला जाता है कि स्कूल में जो भी हो रहा है वो अपने घर पर और प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करना है। इस अराजकता के माहौल में डरे सहमे छोटे-छोटे बच्चे स्कूल तक जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वही स्कूल प्रबंधन को इस तरह के वातावरण पर विचार कर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, और स्कूल में चल रहे अराजकता के माहौल पर कड़ाई से दिशा निर्देश देना चाहिए, लेकिन प्रबंधन को तो मोटी रकम मिल ही रही है, स्कूल के अंदर क्या चल रहा उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है, तो क्या ड्रीम इंडिया स्कूल अब जंग का मैदान बन गया है...? और इसी तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा यह बड़ा सवाल है..?

बागेश्वर बाबा के बाद मोहन सरकार की मंत्री निकाल रही धार्मिक यात्रा

नगरीय प्रशासन और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी 50 किलोमीटर चलेंगी पैदल

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ
सतना, मोहन सरकार में नगरीय प्रशासन और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने पैदल यात्रा शुरु की है। यह यात्रा प्रतिमा बागरी उनके विधायक बनने और मंत्री पद मिलने की मन्नत मां शारदा से की थी। उनकी मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने एक साल यात्रा शुरु की है। इस यात्रा की चर्चा विंध्य के सियासी गलियारों में जमकर हो रही है।

मैहर माता मंदिर में होगा यात्रा का समापन- मंत्री प्रतिमा बागरी की यात्रा का समापन मैहर माता मंदिर में होगा। जहां पूजा-पाठ करने के बाद उनकी यात्रा का बुधवार को समापन होगा। ये यात्रा सतना और मैहर से होकर गुजरेगी। जिसमें कई स्थानीय बीजेपी नेता शामिल होंगे। बता दें कि, प्रतिमा बागरी सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह साल 2023 में पहली बार विधायक चुनी गई। जिसके बाद उन्हें मोहन सरकार में राज्यमंत्री बनाया गया।

कैम्प से सम्बन्धित राजस्व ग्राम के समस्त कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दिन हो सुनिश्चित :- डीएम मनीष बंसल

04 दिसम्बर से 16 जनवरी तक समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे फार्मर रजिस्ट्री कैम्प

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल ने बताया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में कृषि एवं राजस्व विभागों के द्वारा 04 दिसम्बर से 16 जनवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। इन कैम्पों के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जायेगी जिससें किसानों को कृषि तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ बिना अभिलेखों के ही सीधे प्राप्त हो सकेगा साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19 वीं किस्त उन्ही किसानों को जारी की जायेगी जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद के समस्त कृषक बंधुओं से अनुरोध किया है कि कैम्पों में अपना आधार कार्ड, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल, एवं अपनी समस्त खतौनी ले जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवां ले। कैम्प में सर्वप्रथम कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा किसान का आधार व अन्य डाटा वेरीफाई किया जायेगा तत्पश्चात लेखपाल के द्वारा भूमि का डाटा वेरीफाई किया जायेगा। इन कैम्पों मे पंचायत सहायक व ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा फैमिली आई0डी0 भी बनायी जायेगी। डीएम मनीष बंसल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैम्प के सफल संचालन हेतु कैम्पों की सूचना ग्राम प्रधानों को समय से उपलब्ध कराई जाए। सभी ग्राम प्रधान कैम्प से पूर्व सभी किसानों को अवगत कराकर अधिक से अधिक अपने ग्राम की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाये। उन्होंने निर्देश दिए कि कैम्प से सम्बन्धित राजस्व ग्राम के समस्त कृषक की फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दिन सुनिश्चित हो। समस्त कैम्पों में सम्बन्धित ग्राम के पंचायत सहायक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कृषक बंधु आयोजित कैम्प का अधिकाधिक लाभ उठाएं।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर में शराबखोरी करते युवकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ
अनूपपुर, जिला पुलिस अधीक्षक अनूपपुर, श्री मोती उर रहमान जी के निर्देशानुसार, जिले के विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शराबखोरी या किसी भी प्रकार के असामाजिक कृत्य की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, सोमवार रात को कोतवाली पुलिस ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर के बरामदे में शराब का सेवन कर रहे तीन युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

घटना का विवरण- रात्रि करीब 10:00 बजे टी.आई. कोतवाली, अरविंद जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार साहू और आरक्षक कपिल सोलंकी व गिरीश चौहान ने चेकिंग के दौरान, जैतहरी रोड स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राथमिक शाला के बरामदे में तीन युवकों को शराब पीते हुए पकड़ा। मौके से शराब की बोतल, पानी के पाउच, डिस्पोजल गिलास और नमकीन आदि बरामद किए गए।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण-1. आशुतोष पनगरे, पिता संतोष कुमार पनगरे, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, उज्ज्वला कॉलोनी, अनूपपुर। 2. शुभ शर्मा, पिता उत्तम शर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 09, बिहारी कॉलोनी, अनूपपुर। 3. अक्षत यादव, पिता रविशंकर यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी बिहारी कॉलोनी, अनूपपुर।

आरोपियों पर कार्रवाई- आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 510/24, धारा 36(ब) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक की अपील- पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान ने नागरिकों से अपील की है कि यदि जिले के किसी भी विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र में कोई व्यक्ति शराबखोरी या अन्य असामाजिक गतिविधि करता है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम में दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा के पवित्र स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त रखा जा सके, पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरके पब्लिक स्कूल में चल रही तीन दिवसीय खेल स्पर्धा के अंतिम दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर दिखाई अपनी-अपनी प्रतिभा

खो-खो में दून हिल्स एकेडमी की छात्राएं अव्वल रहीं, बैडमिंटन डबल्स में आरके पब्लिक स्कूल की छात्रा रिमझिम व आयुषी और एकल बैडमिंटन में मेपल्स एकेडमी की स्नेह प्रथम रहीं

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर । देवबंद, आरके पब्लिक स्कूल में चल रही तीन दिवसीय खेल स्पर्धा आज संपन्न हुई। अंतिम दिन विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। खेलों में रोजगार के अवसर भी तलाशे जा सकते है। खेल महोत्सव में अंतिम दिन खो-खो में दून हिल्स एकेडमी की छात्राएं अव्वल रहीं। बैडमिंटन डबल्स में आरके पब्लिक स्कूल की छात्रा रिमझिम व आयुषी और एकल बैडमिंटन में मेपल्स एकेडमी की स्नेह प्रथम रहीं। क्रिकेट मैच में दून वैली स्कूल, जनता इंटर कालेज, आरके पब्लिक स्कूल और दून हिल्स स्कूल के बच्चों का शानदार प्रदर्शन रहा। विद्यालय के चेयरमैन राजेश चौहान, डा. कुलदीप राणा, प्रधानाचार्य डा. नीरज लता शर्मा व उपप्रधानाचार्या मोनिका कपूर ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष विपिन गर्ग, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि विजय त्यागी, गन्ना समिति के चेयरमैन डा. उपेंद्र चौधरी, शिवराज सिंह रोड, कुलदीप सैनी, रविंद्र पुंडीर, सोनित कश्यप, मनीष त्यागी आदि मौजूद रहे।

निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून हाईवे के एलिवेटेड रोड का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण

सीएम धामी ने निर्माण कंपनी के अधिकारियों से कार्य की प्रगति तथा इसमें इस्तेमाल की जा रही तकनीक के बारे में ली जानकारी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर (बिहारीगढ़), निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून हाईवे के एलिवेटेड रोड का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कंपनी के अधिकारियों से कार्य की प्रगति तथा इसमें इस्तेमाल की जा रही तकनीक के बारे में जानकारी ली। देहरादून से सहारनपुर के सरसीना गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार से एलिवेटेड रोड से गुजरे। उन्होंने इस दौरान एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है केवल लाइटिंग का कार्य शेष है। इसे भी 15 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में एक सप्ताह तक इसे वाहनों के ट्रायल के लिए खोला गया था। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने एलिवेटेड रोड के निर्माण में इस्तेमाल हुई आधुनिक तकनीक व पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया।

हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम में हुई कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित

कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनूपपुर, रविवार को हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कल्याण मंडप क्लब चचाई में किया गया, यह कार्यक्रम भारत सरकार एवं तीनो आयल कम्पनी हिंदुस्तान पैट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 12 प्रतिभागियों द्वारा खाना बनाया गया तथा अनूपपुर मुख्यालय की भुवनेश्वरी गैस एजेंसी के देख रेख में हुआ । कार्यकम में मुख्य अभियंता विद्युत मंडल चचाई एम एल पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम आयोजकों तथा सभी प्रतिभागियों का हौंसला बढ़ाया। कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान पैट्रोलियम के वरिष्ठ बिक्री अधिकारी सतना शुभन कुमार गुप्ता की देख रख में किया गया। शुभन कुमार गुप्ता द्वारा सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई तथा जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कुकिंग में विजयी तीन प्रतिभागियों जिसमें प्रथम स्नेहा कोष्टि, द्वितीय पारुल राजपूत तथा तृतीय मनीषा यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जज के रूप में सीमा सिन्हा खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अनूपपुर , राजबहोर सोनी उपस्थित रहे, कार्यक्रम का संचालन शुभन कुमार गुप्ता द्वारा किया गया।

त्राहिमाम : 15 दिनों से ठप्प जलापूर्ति पेयजल को मोहताज़ यात्री

तत्काल निराकरण को मोटर मजदूर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, संभागीय मुख्यालय के न्यू बस स्टैंड में बूंद बूंद पानी के लिए यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है,मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि न्यू बस स्टैंड में प्रतिदिन 120 बसों का आना-जाना है, 15 दिन से यहां पानी सप्लाई बंद होने से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तेजबलि शर्मा ने आवेदन देते हुए कलेक्टर को बताया कि न्यू बस स्टैंड में पिछले 15 दिनों से पानी सप्लाई बंद है, श्री शर्मा के अनुसार उन्होंने जिस दिन पानी की सप्लाई बंद हुई थी, उस दिन से आज तक कई बार नगर पालिका में आवेदन देकर इस समस्या का समाधान करने के लिए निवेदन किया लेकिन अब तक कोई सुधार न हो सका। अध्यक्ष ने कहा कि मैने स्थानीय विधायक से मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत करा चुका हूं,लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला गया है। पानी सप्लाई न होने से आने व जाने वाले यात्रियों को काफी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द से जल्द बस स्टैंड में पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई तो मोटर मजदूर यूनियन इस पर आंदोलन करने को मजबूर हो होगा। संभागीय मुख्यालय में स्थित न्यू बस स्टैंड में पानी न मिलने से हजारों यात्रियों को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जवाबदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनियन के अध्यक्ष ने कलेक्टर को जनसुनवाई में ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पानी चालू करवाने की मांग की है।

इनका कहना है

दो मशीने खराब होने से बस स्टैंड में पानी सप्लाई नहीं हो पाई है। सुधार के लिए टीम लगी हुई है ,जल्द से जल्द पानी की सप्लाई बस स्टैंड में हो सकेगी।

शरद द्विवेदी, इंजीनियर, नगर पालिका परिषद शहडोल

सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी वैन

तिखवा सचिव अमरेंद्र सिंह मरावी सड़क दुर्घटना में मौत

शहडोल, तेज रफ्तार ओमनी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे टकरा गई उसमें सवार पंचायत सचिव की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वैन चालक घटना के बाद से ही फरार है। जयसिंहनगर के कनाडी से वैन में सवार सचिव अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र के जोरा गांव में घटी है।

ट्रक में हुई भूसा आधी वैन... दरअसल ब्यौहारी थाना क्षेत्र के जोरा गांव मे सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था तभी तेज रफ्तार मारुति वैन क्रमांक एमपी 18 बी बी 1484 ट्रक के पीछे से टकराते हुए वैन का आधा हिस्सा ट्रक के पीछे घुस गया, ड्राइवर सीट के बगल में बैठे ब्यौहारी जनपद के तिखवा पंचायत सचिव अमरेंद्र सिंह मरावी की इस घटना में मौत हो गई। घटना जब घटी तो काफी तेज आवाज आई जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग मौके पर दौड़ पड़े और पंचायत सचिव को निकालने की कोशिश की, लेकिन वाहन ट्रक के पीछे आधा घुस गया था और सचिव की मौके पर ही मौत हो गई थी, वाहन चालाक घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच पड़ताल कर रही है।

इनका कहना है - वैन में सवार तिखवा सचिव अमरेंद्र सिंह मरावी कनाडी गांव से आपने घर तिखवा जा रहे थे, तभी रास्ते मे जोरा गांव मे यह दर्दनाक हादसा हुआ है। वैन में कितने लोग सवार थे, यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस को जब मामले की जानकारी लगी थी तो पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहन में पंचायत सचिव का शव मिला। वैन चालक का पता लगाया जा रहा है, सड़क किनारे खड़े ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है, ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की जाएगी, सचिव की मौत मामले पर मर्ग कायम किया गया है।

अरुण पाण्डेय, थाना प्रभारी, थाना ब्यौहारी, शहडोल

मानसिक स्थिरता को खेल करता है विकसित- कमिश्नर

शहडोल जिले के खिलाड़ी हर विधाओं में पारांगत- कलेक्टर

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, बैंगलोर कर्नाटक में आयोजित ओपन शौर्य अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शहडोल जिले के विजेता खिलाड़ियों को आज कमिश्नर कार्यालय के अमरकंटक सभागार में कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता एवं कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों से चर्चा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता और टीम वर्क की भावना को भी विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल आवश्यक है। खिलाड़ियों से चर्चा करते हुए कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कहा कि शहडोल जिले के खिलाडी कराटे, फुटबाल, क्रिकेट जैसे अन्य विधाओं में पारांगत है। कलेक्टर ने कहा कि शहडोल जिले के खिलाड़ी हर खेलों में आगे बढ़े और अपने गांव, कस्बे, जिले, प्रदेश, देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करें। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को कमिश्नर एवं कलेक्टर ने ट्रैक शूट भी वितरित किये। इस अवसर संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश, जिला शिक्षा अधिकारी एमएल पाठक, सहायक संचालक खेल रईस अहमद, मैंगलोर कर्नाटक में आयोजित ओपन शौर्य अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में विजेता खिलाडी व कोच उपस्थित थें।

न्यूनतम वेतन पर दिया गया स्टे हाईकोर्ट इन्दौर खण्ड पीठ ने किया खारिज

मजदूरों को 1 अप्रैल 2024 से एरियर सहित भुगतान किये जाने की किया मांग - सीटू

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनूपपुर, तमाम जद्दो -जेहाद और सैकड़ो धरने और प्रदर्शनों के बाद सरकार ने 10 वर्ष के बाद वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रैल 2019 के बजाय अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन की घोषणा की थी, उस पर भी कुछ कारखाने मालिकों के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से न्यूनतम वेतन न दिया जाए इसके लिए स्टे लिया था । सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी और प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान द्वारा उक्त स्टे के खिलाफ सीटू की ओर से पूरे प्रदेश भर में सरकार पर दबाव पैदा करने के लिए लगातार प्रदेश के जिलाधीश और श्रम विभाग के ऑफिसों पर धरने दिए और इसके साथ-साथ इंदौर हाई कोर्ट में सीटू इंटरवीन बनी । सीटू की ओर से विद्वान अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन के सवाल पर मजदूरों का पक्ष मजबूती से रखा । आज हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के माननीय न्यायाधीश श्री विवेक रुसिया और माननीय न्यायाधीश श्री गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने स्टे को खारिज कर दिया जो कि मजदूरों की एक ऐतिहासिक जीत है। सीटू नेता रामविलास गोस्वामी और प्रमोद प्रधान ने मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त से मांग करते हुए कहा कि यह स्थगन एक अप्रैल से हो रहे भुगतान के खिलाफ था जो खारिज हो गया है अब 1 अप्रैल 2024 से श्रमिकों का एरियर सहित भुगतान सुनिश्चित करायें । अनूपपुर सीटू के अध्यक्ष रामू यादव महासचिव इंद्र पति सिंह कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा सीटू के कार्यकारी अध्यक्ष कामरेड जुगुल किशोर राठौर अध्यक्ष संयुक्त ठेकेदारी मजदूर युनियन सीटू जैतहरी, कामरेड अफसाना बेगम उपमहासचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एकता युनियन अध्यक्ष ,देवेंद्र कुमार निराला अध्यक्ष के एस एस , संध्या शुक्ला आंगनबाड़ी महासचिव, आर एस यादव कार्यवाहक अध्यक्ष शारदा सिंह तेज भान पांडेय कल्याण मंडल सदस्य राधेश्याम यादव ज्ञानेंद्र सिंह लखपती सिंहसहायक सचिव एल बी सिंह उत्तम तिवारी शिवानंद मांझी उपाध्यक्ष के एस एस सीटू जमुना कोतमा क्षेत्र राजेंद्र विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष ममता विश्वकर्मा आशा ऊषा सहयोगिनी एकता युनियन सीटू अध्यक्ष रामायण पटेल सचिव मगलू साहू अध्यक्ष राजेश सिंह कल्याण मंडल के सदस्य के एस एस हसदेव क्षेत्र, तथा संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू के महासचिव कामरेड सहसराम चौधरी, कोषाध्यक्ष कामरेड रमेश सिंह, राजकुमार राठौर, मोतीलाल रजक, भीमसेन केवट, कमलेश चन्द्रा, सुशील कुमार, कैलाश सिंह राठौर, चमेली सिंह गोड़, कुसुम राठौर, ममता प्रजापति ने इस जीत को मजदूर वर्ग के संघर्ष का ऐतिहासिक जीत बताया है । अब मजदूरों को 2225 रुपए प्रति माह तक विभिन्न कारखानों में काम करने वाले मजदूर और शासकीय क्षेत्र में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने वेतन वृद्धि देय होगी। सीटू ने आम मजदूर और कर्मचारियों को एकता बनाए रखने की अपील की है।

लोकसेवा एवं सीएम हेल्पलाइन पर नहीं चलेगी लापरवाही

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सभी विभागों की विभागवार समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में आने वाली शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करना हमारी जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण होना चाहिए। जिला स्तर के अधिकारी अपने विभाग संबंधित शिकायतों को देखें तथा प्राथमिकता के साथ शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

लंबित शिकायतो को तरजीह.. कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान केलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा अधिनियम अंतर्गत लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत समय सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। शिकायतों का समय-सीमा के भीतर ही निराकरण करें।

सीएम हेल्पलाइन में ना हो लापरवाही... सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें तथा शिकायतों के निराकरण करने की कार्यवाही करे। उन्होनें अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त कोई भी शिकायत अनअटेन्डेंट नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग,जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर अरविंद शाह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ददिया धान खरीदी केंद्र में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ लालबर्रा, नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम ददिया में धान खरीदी केंद्र में 2 नवंबर को किसान संघ के तत्वावधान में ददिया सोसायटी के अंतर्गत आने वाले ददिया व बम्हनी के किसानों ने एक जुट होकर ददिया खरीदी केंद्र पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और सरकार से कहा कि हम अपना हक मांगते ना ही किसी से भीख मांगते,धरना प्रदर्शन में शामिल जनपद सदस्य प्रतिनिधि मनीराम भोयर ने बताया कि करीब एक साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और वर्तमान सरकार ने किसानों से 31सौ क्विंटल रूपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है। वहीं किसानों का आरोप है कि सत्ता में आने से भाजपा सरकार अपनी घोषणा के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं कर रही है। वहीं सरकार से मांग है कि किसानों का धान 31 सौ रुपए में खरीदी करें। धरना प्रदर्शन में पहुंचे किसानों ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव बालाघाट आऐ थे। उन्होंने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद 31सौ रूपए की जो 917 रूपए की राशी बकाया है। वह प्रदान दी जाएंगी। लेकिन आज तक किसानों को वह राशि नहीं मिली है। जबकि अब फिर से 2300 सौ रुपए में धान खरीदी होनी है। यह किसानों के साथ वादाखिलाफी है। यही याद दिलाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। और आगे भी यह धरना प्रदर्शन किया जाऐगा। साथ ही सभी किसान भाइयों से आह्वान किया है कि वह उपार्जन केन्द्रों में जाकर धान न बेचें। ताकि सरकार किसानों की मांग पूरी कर सके।

इस धरना प्रदर्शन करने मे मनीराम भोयर जनपद सदस्य प्रतिनिधि,राजेन्द्र भलावी सरपंच प्रतिनिधि, तुलसीराम बोपचे पुर्व जनपद सदस्य,कृष्ण कुमार मोहबे पुर्व सरपंच,भोजलाल हरिनखेड़े, नरेंद्र भोयर, दिनेश बिसेन, श्रीराम बुराडे, प्रेमलाल राजुरकर,नवीन कडौकर, बेनीराम कड़ोकर, लकेश पंचेश्वर, भीवजी रहांगडाले, श्रीभुवन बिसेन, राजेन्द्र धार्मिक, प्रमोद हरिनखेडे, विरेन्द्र बोपचे, दुर्गा आश्वाले, सजंय आश्वाले, श्रीराम कड़ोकर,दिनेश श्रीरसागर, लेखराम बनकर,युवराज ठाकरे, लेखराम तुमसरे,टेकराम आश्वाले,दिपेश बोपचे,हंसराज भोयर,खुबचंद गोमसे,प्रमोद बोपचे,हेमराज भोयर,मधुकर कड़ोकर,सहित ददिया व बम्हनी के किसान मौजूद रहे।

दिव्यांग सरस्वती की पढ़ाई की राह हुई आसान

आंखों से दिव्यांग सरस्वती अठ्या को कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की मदद से मिला सहारा, रीवा में रहने, खाने और पढ़ने की मिलेगी सुविधा

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया अगारा गांव की सरस्वती आठ्या, जब मैं स्कूल के निरीक्षण के लिए गया था, तब यह बच्ची क्लास में बैठी हुई मिली थी, यह किसी दूसरे दिव्यांग संस्थान में पढ़ाई करती थी, लेकिन वह संस्थान बंद हो गया, जिसके बाद इसे अपने गांव जाना पड़ा। कलेक्टर ने देखा यह बच्ची तीसरी क्लास के बाकी सामान्य बच्चों के साथ बैठी है, जब इससे प्रश्न पूछे तो बहुत अच्छे से जवाब दिए, इसको ब्रेल में भी बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, बच्ची बहुत प्रतिभाशाली है। कलेक्टर ने बताया पता करने पर पाया कि यह बच्ची जन्म से दिव्यांग है, इनकी दोनों आंखें नहीं है, और आंखों से शत-प्रतिशत डिसेबल्ड है। इस बच्ची को आज यहां बुलवाया गया था आंखों का दोबारा चेकअप करवाया गया, जिससे कंफर्म हुआ की आंखों में उपचार की कोई गुंजाइश नहीं है, इनके लिए हमने दो काम किए हैं पहला चलने के लिए एक स्टिक आती है, मैंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इस बच्ची को स्टिक दिलवा दी जाए। इसके अलावा रीवा में राज्य सरकार ने इस तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए रहने, खाने और पढ़ने सभी चीजों की व्यवस्था की है, वहां पर एक नया संस्थान बनाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर रीवा से बात करके इस बच्ची की व्यवस्था वहां पर करने का आग्रह किया था, तो उन्होंने मुझे सहज स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि इनका आवेदन भिजवा दें, तो इनका एडमिशन करा देंगे। जल्द ही इस बच्ची का एडमिशन वहां पर हो जाएगा, इसके माता-पिता भी इसे वहां भेजने के लिए तैयार है, जिससे इस बच्ची की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ठीक से हो पाएगी।

कानाफुंसीः आरआई दे रहा अफसरों को विधायक की धुडकी

भूमाफियाओं से साठ-गांठ, पक्षकारों की बढ़ी तकलीफ़

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ कहीं खसरे में अंकित रकबा घटा तो कही पट्टे की भूमि लापता, बिना चौहद्दी हो रही रजिस्ट्री, राजस्व रिकॉर्ड में जमकर हेरफेर, जिले की जनता शिकायत लेकर दफ्तर दफ्तर काट रही चक्कर, लापता आर आई लगे भू-माफियाओ की जी हुजूरी में, आरआई ने दे दिया ठेके पर राजस्व निरीक्षक भवन या दलालों की कर दी अवैध नियुक्ति। पीड़ित फरियादियों की दयनीय स्थिति, पढ़ें पूरी ख़बर....

शहडोल। जिले में लगातार राजस्व अमले की भूमाफियाओं से साठ-गांठ से तंग हाल जनता का जीना हराम है कहीं किसी की पट्टे की भूमि गायब है तो कहीं किसी के खसरा अंश भाग में दर्ज रकबा घटा दिया गया, तहसीलदार कार्यालय में बीते कुछ दिनो से भू-माफियाओ एवं शासकीय राजस्व अमले की साठ-गांठ से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है आलम यह है कि सरकारी व असहायों की भूमि पर कब्जा करना यहां के लोगों की नीयत में सुमार हो चुका है। दरअसल इस कार्य में खद्दरधारी ही नहीं बल्कि टाई वाले (अधिकारी-कर्मचारी) भी शामिल हैं। इसकी गवाही कोई और नहीं यहां दर्ज मुकदमे दे रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य अंचल में आदिवासियों की ही दुर्गत है यहां एकड़ से डिसमिल में बिना डायवर्सन भूमि बिक्री का खेल जारी है भू माफिया का यह खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि राजस्व मामले में यही तहसील और अनुविभाग कार्यालय है जहां पर लोकेश जांगिड़ ने परत दर परत भू-माफियाओं को आड़े हाथों लेते हुए नकेल कसी हुई थी जिसके बाद खद्दर ओढ़े हुए लोगों ने राजधानी में नाक रगड़ रगड़ कर तबादला करवा दिया था। लेकिन इस बीच जीरों टांलरेस को लेकर सख्ती और शिकायत पर कार्यवाही का खौफ दलाली देखते बनता था।

तो सीएम का आदेश हुआ बेअसर... बहरहाल ऐसे मामलों में अब तो सीधे तौर पर सूबे की मोहन यादव सरकार का फैसला है कि लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले और शासकीय भूमि कब्जा करने वाले लोगो प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए बाकायदा नामजद सूची तैयार की जानी चाहिए थी। इस आदेश का असर शहडोल जिले में तो नहीं दिखाई दे रहा है।

कृषि भूमि पर बहुमंजिला इमारते... कृषि भूमि पर नियमविरुद्ध कालोनी विकसित करने की बात आम हो गई है जबकि इसके चलते शहडोल जिले के सरकारी खजाने में हर साल करोड़ों रुपए की सेंध लगाने का गोरखधंधा चुनिंदा पटवारी और आर आई की बदौलत चल रहा है, मरना नदी के बगल में तमाम गगन चुम्बी इमारते जिस भूमि में बानी है राजस्व रिकॉर्ड में आज भी कृषि भूमि ही है, यह चमत्कार पटवारी के कृपा दृष्टि बगैर संभव नही है, जिसमें सबसे पहला नाम आर आई वीरेंद्र सिंह का है यह व्यक्ति खुद को उमरिया मानपुर विधायक सुश्री मीना सिंह की धुडकी देकर एक ओर जिले के जिम्मेदार अफसरों को खुद पर हावी नहीं होने देता तो वहीं राजस्व रिकॉर्ड में लगातार छेड़छाड़ करते हुए टेबिल के नीचे वाली लाखों रुपए की कमाई भी मानपुर विधायक के नाम पर करता है मज़े की बात तो यह है कि इसके साथ साथ राजेश विश्वकर्मा नामक आर आई पटवारियों की नब्ज़ पकड़कर मात्र भू-माफियाओ को लाभ दिलाने एड़ी-चोटी का जोर लगाए रहते हैं। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि दो? आर आई और पटवारी जिला कलेक्टर पर भारी है इधर इनकी टेरिटरी वाले अनुभाग में रहने वाले वासिंदा त्राहिमाम त्राहिमाम करता नजर आ रहा है द्य

यहाँ उफान पर दलाली... वहीं दलालों और भू-माफियाओ की चांदी है इस मामले में टाप टू बाटम इनकी राजस्व रिकॉर्ड में अनाप-शनाप दख़ल जोड़-तोड़ और भूमाफियाओ के घालमेल से सभी त्रस्त है लोगों की अमूमन शिकायत राजस्व रिकार्ड में गड़बड़ी को लेकर आता है तो कहीं आस पड़ोस भूमि विवाद में द्वंद युद्ध चलता थाने पहुंच रहा है तो कहीं लोग मौत के मुहाने तक पहुंच रहे हैं हालही में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भू-माफियाओ से तंग आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी इसके बाद पीड़ित परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था पुलिस कप्तान की सूझबूझ और तत्कालीन कलेक्टर को संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा। हालांकि मामले को रफा-दफा कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि मामले के पीछे कई वजह क्या है प्रशासनिक अधिकारियों को जानने और समझना चाहिए। कि आखिर कैसे कोई भी बिना चौहद्दी भूमि बेची जा रही है पटवारी प्रतिवेदन, मौकापंचनामा, सर्च रिपोर्ट में भौतिक निरीक्षण इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों को जानबूझकर छोड़कर रखा जाता है। जो कहीं ना कहीं बिक्रेता को धोखाधड़ी करने का मौका देने का काम करता है। इनकी इसी तरह की करतूत नवागत कलेक्टर की भी आंख में धूल झोंकने का काम करने लगी है विक्रेता क्रेता से बड़ी आसानी से ठगी कर देता हैं।

पहुंचने लगी है शिकायते... हालांकि इस मामले में अब जब बिक्री भूमि क्रय करने वाले लोगों की भीड़ ने कलेक्टर कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया तब कहीं जाकर आर आई पटवारियों के खेल खेलने के पीछे का गुड़ रहस्यमय तरीकों का खुलासा हुआ कि आखिर कैसे सरकारी वेतन पाने वाले आर आई ईमानदारी का चोला ओढ़कर भू-माफिया के हितार्थ समर्पित उनकी चाकरी करते है।

लापरवाही अनदेखी की पराकाष्ठा..... वहीं नगर में ऐसी कई कालोनियां हैं जिनके अवैध प्लाटिंग के मामले विभागों में लंबित है। एमपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के नियमानुसार किसी भी कालोनाइजर को जमीन की प्लाटिंग करने से पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा प्लाट बेचने से पहले वहां जन सुविधाओं से जुड़ी चीजें नाली, सड़क, बिजली व पानी का इंतजाम, सीवर, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नगर की कई कालोनियां आज भी इन मूलभूत सुविधा से वंचित हैं।

जबकि सजा का भी प्रावधान.... रेरा के नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई का प्रावधान है। गड़बड़ी करने वालों पर जहां रेरा उसकी योजना की लागत का दस प्रतिशत तक जुर्माना कर सकती है वहीं किसी मामले में एफआइआर होने पर तीन साल की सजा का भी प्रावधान एक्ट में है। रेरा के अनुसार एक्ट की वजह से यह भी तय है कि जिनका पंजीयन रेरा में होगा, उन कालोनाइजर पर लोग भरोसा कर सकेंगे।

राजस्व का भारी नुकसान..... क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई कालोनाइजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दो-चार एकड़ जमीन का डायवर्शन कराकर 10 से 15 एकड़ जमीन पर कालोनी का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रेरा के कायदे कानून के मुताबिक़ भूमि के डायवर्शन हो जाने के बाद ही उस भूमि का लेआउट पास किया जाता है लेकिन रेरा के नियमों को भी दरकिनार कर बिना डासवर्शन वाली भूमि का ले-आउट पास कर दिया जा रहा है। वही हाल ही में थाने तक पंहुचा एक मामले ने राजस्व सहित पुलिस प्रशासन की नींदे उड़ा दी एक चर्चित भूमाफिया ने छत्तीसगढ़ के पुलिस जवान को वन भूमि का पट्टा बनाकर दे दिया, सूत्र बताते है कि बैंक लोन इत्यादि की पड़ताल में वनभूमि का पर्दाफाश हुआ, अब जब भूमाफिया पर शहडोल सहित अन्य थानों में शिकायत भरी पड़ी है तो घुनघुटी की भूमि मामले की ठगी की शिकायत को स्थानीय थाना स्तर पर सेटिंग प्रलोभन के चक्कर में दबा दिया गया है, कहा यह भी जा रहा है भूमाफिया ने डबल कीमत की और दुशरी भूमि का प्रलोभन दिया गया है जिसका बाकायादा ईस्टाम्प में लिखा पढ़ी भी किया गया है, अब प्रश्न के नाक के नीचे सरकारी और फॉरेस्ट की भूमि खतरे में है तो आम आदमी भूमाफियाओ से अपनी भूमि कैसे सुरक्षित रख सकता है ल

लगातार बढ़ता अपराध... दरअसल सच्चाई जो सामने आई है उससे जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की नींद हराम हो सकती है, हर तीसरी रजिस्ट्री में चौहद्दी बिना दर्ज नामांतरण हो रहा है और यह सब कुछ कलेक्टर की नाक के नीचे जाने कैसे भू-माफियाओ का सिंडिकेट सेंध लगा जा रहा है। अगर राजस्व अमले की करतूत पीड़ित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, नगर के सुधिजनो का इस मामले में कहना है कि पीड़ित फरियादियों की शिकायतो को लेकर यद्यपि शासन स्तर पर समय रहते मंथन ना किया गया तो लगातार बढ़ता अपराध और अनहोनी घटनाक्रम से जिले को यूंही दो चार होते रहने की मजबूरी बन जाएगी, इनकी करतूत से ना जाने कितने परिवार थाना कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं जिला प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो जनता अब समझना शुरू कर दें कि माफियातंत्र के आगे तमाम जिम्मेदार अफसरों ने घुटने टेक दिए।

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सराफा व्यवसायियों से कहा जितनी भी तरह के दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है

वह सब दस्तावेज 15 दिन के अंदर नगर पालिका को दिये जायें

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की मौजूदगी में आज शाम दमोह के सराफा व्यवसायियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई । कलेक्टर को लगातार इस बारे में शिकायतें प्राप्त होती थी कि सराफा मार्केट क्षतिग्रस्त है और उससे नुकसान हो सकता है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है। इस सिलसिले में चर्चा के लिए सभी सराफा व्यवसायियों और नगरपालिका सीएमओ, एस.डी.एम. और नगर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में कलेक्टर कोचर ने कहा बैठक में सभी से चर्चा करके कुछ निर्णय लिए है, जिनमें कल सीएमओ नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी से चिट्ठी लिख करके पीडब्ल्यूडी का पूरा प्रपोजल निकलवाएंगे की कब पीडब्ल्यूडी ने इसको क्षतिग्रस्त घोषित किया था, उसके पूरे डाक्यूमेंट्स निकलवाए जाएंगे। यदि वो

डाक्यूमेंट्स इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई होगी या उपलब्धता नहीं होगी, तो फिर ऐसी स्थिति में नए सिरे से प्रयास करेंगे या विचार करेंगे की फिर से एक बार पूरी उसकी जांच तकनीकी विशेषज्ञों से करायें। कलेक्टर ने कहा जितने भी सराफा व्यवसायी है, उनको नगर पालिका के द्वारा एक नोटिस जारी किया जा रहा है, कि उनकी लीज डाक्यूमेंट्स से संबंधित जो भी दस्तावेज उनके पास है, जितनी भी तरह के दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है, वो सब दस्तावेज 15 दिन के अंदर नगर पालिका को दे, ये दोनों कार्रवाई होने के बाद फिर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

बंग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन रैली आज

सनातन चेतना मंच दमोह की बैठक संपन्न

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, सकल हिन्दू समाज जिला दमोह के समस्त सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष एवं प्रमुखों जनों की बैठक सनातन चेतना मंच के बैनर तले स्थानीय नीलकमल गार्डन में आयोजित की गई। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़े जाने के साथ ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आज बुधवार को सनातन चेतना मंच जिला दमोह के द्वारा विशाल धरना,ज्ञापन, रैली का आयोजन किया गया है। वहीं दमोह में सनातन चेतना मंच के के द्वारा आधे दिन का उपवास का आव्हान भी किया गया है। इसके अलावा रैली के दौरान काली पट्टी बांध कर भी विरोध प्रकट किया जाएगा। मंगलवार की दोपहर में सनातन चेतना मंच दमोह के द्वारा एक बैठक आयोजित कि गई इस बैठक का विषय था कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रें अत्याचार तत्काल बंद करवाने एवं इस्कान के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को अन्याय पूर्ण कारावास से मुक्त करवाने की मांग की गई बांग्लादेश

में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले, हत्याएं, लूट आगजानी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंकत चिंताजनक हैं। जिसकी सनातन चेतना मंच इसकी कड़ी भर्त्सना करता हैं। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसिया इसे रोकने के स्थान पर केवल मूकदर्शक बनी हुई हैं बांग्लानदेश के हिन्दुओं के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभरता दिख रहा है। ऐसे ही शांति पूर्ण प्रदर्शनों में हिन्दुओं का नेतृत्व कर रहें इस्कॉन के सन्यासी चिन्मेय कृष्णीदास को बांग्लादेश सरकार द्वारा जेल भेजना अन्योय पूर्ण हैं। सनातन चेतना मंच बांग्ला देश सरकार से यह आव्हन करता है कि वह सुनिश्चित करें कि बांग्लाजदेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हों तथा चिन्मय कृष्णिदास को कारावास से मुक्तर करें। उक्त मांगों को लेकर सनातन चेतना मंच की बैठक में तय किया गया कि आज 04 दिसम्बर 2024 दिन बुधवार जिला केन्द्र पर धरना प्रदर्शन दोपहर 01 बजे से स्थानीय तहसील ग्राउंड पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित कर विशाल रैली के साथ ज्ञापन देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा,सभी समाज प्रमुखों,सभी समाज संगठनों, गणेश उत्सव समितियां,गायत्री परिवार, सभी समाज सम्मिलित होकर संत समाज के नेतृत्व में रैली मेंअनुशासन के साथ चलेगें। ज्ञापन रैली तहसील ग्राउंड से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुये कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी। वहां सनातन चेतना मंच जिला दमोह के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।

हम होगे कामयाव जागरूकता अभियान के अंतर्गत सायवर सेल दमोह एवं एस. जे.पी.यू. की टीम द्वारा स्कूल एवं कम्प्यूटर संस्था के छात्र एवं छात्राओ को किया जागरूक

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे हम होगे कामयाव जागरूकता अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सायवर सेल दमोह, SJPU दमोह द्वारा महिला सुरक्षा , सायवर सुरक्षा के विषय में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सिद्धार्थ कंप्यूटर संस्था और जे.पी.बी. कन्या शाला में आयोजित हुआ। इस अभियान के दौरान छात्रों और छात्राओं को सायवर फ्रॉड जैसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन क्क्य फाइल्स, सोशल मीडिया सुरक्षा, ओटीपी फ्रॉड आदि के साथ साथ महिला सुरक्षा, महिला हेल्प लाईन 1090, चाईल्ड लाईन 1098, सायवर हेल्प लाईन 1930 नंबर तथा सायवर पोर्टल www.cybercrime.gov.in के संबंध में जानकारी दी गई तथा सायवर फ्राड होने पर क्या करें और क्या न करें के संबंध में बताया गया । कार्यक्रम में सायवर सेल प्रभारी निरीक्षक अमित गौतम, प्र.आर. सौरभ टंडन, राकेश अठया, आर. रोहित राजपूत, और हेमलता नामदेव ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस अवसर पर सिद्धार्थ कंप्यूटर संस्था के संचालक सिद्धार्थ अग्रवाल, जे.पी.बी. कन्या शाला के प्राचार्य डी.के. मिश्रा और स्कूल स्टाफ सहित स्कूल एवं संस्था के करीब

केजेएस सीमेंट ने मनाया सुरक्षा दिवस, कर्मचारी और श्रमिकों ने ली सामूहिक रूप से सुरक्षा शपथ

श्री निवास मिश्रा । सिटी चीफ मैहर, केजेएस सीमेन्ट मैहर में भोपाल गैस त्रासदी की 40 वीं बरसी पर मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा एवं संरक्षण दिवस मनाया गया , जिसमें कारखाने के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे और सभी ने सामूहिक तौर पर सुरक्षा शपथ ली सुरक्षा दिवस के इस कार्यक्रम को वीपी प्रोसेस राजेश शुक्ला , माइंस प्रमुख वी.एस. राठौर , एचआर प्रमुख विकास रायजादा एवं सिविल प्रमुख बी . के . ठाकुर ने संबोधित किया । कार्यक्रम की प्रस्तावना सुरक्षा अधिकारी प्रमोद पयासी ने प्रस्तुत की । एचआर प्रमुख विकास रायजादा ने अपने उदबोधन में उस गैस हादसे और भोपाल फैक्ट्री में उस दिन की हुई लापरवाही का ब्यौरा दिया जिसकी दुखद स्मृति में मध्यप्रदेश सुरक्षा दिवस मनाया जाता है । श्री रायजादा ने बताया कि रोज की तरह 3 दिसम्बर 84 को भी भोपाल की कीटनाशक बनाने वाली उस मल्टीनेशनल फैक्ट्री में शाम तक सब

कुछ ठीक था । इसी बीच रात के करीब 11 बजे फैक्ट्री में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइट के लीक होने की सुगबुगाहट होने लगी । सबसे पहले यह खबर ऑपरेटर को मिली उसने तुरंत उस जगह का पता लगा लिया , जहां से गैस लीक हो रही थी गैस स्टोर रूम में मौजूद एक पाइप से लीक हो रही थी । ऑपरेटर को लगा यह मामूली रिसाव है , इसलिए उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया और लीकेज वाले पाइप को जुगाड़ से सही कर दिया। शायद उसको यह अंदाजा नहीं रहा कि यह जुगाड़ ज्यादा देर तक गैस के इस रिसाव को बांध कर नहीं रख पायेगा। अगर उसने मसले को गंभीरता से ले लिया होता और तुरंत आपात्कालीन गैस कण्ट्रोल प्रक्रिया को शुरू कर दिया होता तो उतनी बड़ी दुर्घटना न होती और न ही हजारों लोग मारे जाते। प्रोसेस प्रमुख राजेश शुक्ला ने कहा कि जब मनुष्य के शारीरिक संचालन और मस्तिष्क की सोच में अंतर आ जाता है तभी लापरवाही होती है। श्री शुक्ला ने कहा कि औद्योगिक इतिहास में भोपाल गैस का हादसा एक ऐसी ही बड़ी दुर्घटना है जो जरा सी लापरवाही से पैदा हुई थी। सेफ्टी प्रमुख प्रमोद पवासी ने चेयरमैन पवन अहलूवालिया के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने फैक्ट्री में सुरक्षा के हरसंभव उपाय किए हैं। और इसीलिए केजेएस सीमेन्ट शून्य दुर्घटना के अपने लक्ष्य पर स्थिर है सुरक्षा विभाग ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सुरक्षा व सतर्कता संबंधी उनके पोस्टर और स्लोगन के लिए पुरुस्कृत किया जिनमें विजय सिंह , राजेश कुशवाहा दीपक प्रजापति एवं सुखेन्द्र सिंह शामिल थे। दो सुरक्षा गार्डों अनुराग तिवारी एव धीरेन्द्र सिंह को भी विशेष सुरक्षा पुरुस्कार दिए गए फैक्ट्री के कर्मचारियों के बच्चों अनंत सोनी दिव्यांश सिंह, अर्जुन शर्मा, पार्थ खरे, धानेश्वरी उपाध्याय एवं काजल शर्मा को भी पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता में पुरुस्कृत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारीगण सर्वश्री राजेश शर्मा, अनिल राय, रविकांत नम्मी, सतीश दुबे, डॉ . टीएस बघेल, लक्षित सिंह, नवनीत ओझा, सूरज मिश्रा, पियूष त्रिपाठी, मनीष सिंह अदिति तिवारी, शालू तिवारी, संतोष कुमार, दिलीप तिवारी एवं जनसंपर्क अधिकारी निरंजन शर्मा की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही।

अमेरिका ने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले का लिया कड़ा नोटिस

कहा- मौलिक स्वतंत्रता का करो सम्मान

अमेरिका ने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों के बीच धार्मिक और आधारभूत मानवाधिकारों सहित मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान का आह्वान किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत लगातार चिंता व्यक्त कर रहा है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संवाददाताओं से कहा, ''हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। पटेल ने कहा, ''सरकारों को कानून के शासन का सम्मान करने की आवश्यकता है, उन्हें आधारभूत मानवाधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। हम इस बात पर हमेशा जोर देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए। पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''हम इस बात पर बल देते हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनसे अधारभूत मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। इस बीच, अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमन ने एक बयान में कहा, ''बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह पूर्ण दायित्व है कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और हाल में हुए हमलों तथा उत्पीड़न के कारण हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शनों का सार्थक रूप से समाधान करे। 'हिंदूएक्शन के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने निवर्तमान बाइडन-हैरिस प्रशासन से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथियों द्वारा हिंसा को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ''बांग्लादेश से हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अंतरिम सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए संत एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी को हिरासत में जान का गंभीर खतरा है। अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं।

दक्षिण कोरिया में रातभर हजारों लोगों ने सड़कों पर किया हंगामा

6 घंटे में पलटा राष्ट्रपति का फैसला, रद्द किया मार्शल लॉ

इंटरनेशनल डेस्क। दक्षिण कोरिया में मंगलवार देर रात एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा की। इस फैसले ने जनता और संसद में उथल-पुथल मचा दी। भारी विरोध के बीच मात्र 6 घंटे बाद राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मंगलवार रात 11 बजे, राष्ट्रपति यून सुक योल ने अचानक टेलीविजन पर अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष उत्तर कोरिया के एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लागू करना जरूरी है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने आर्मी जनरल पार्क अन सू को मार्शल लॉ कमांडर नियुक्त किया, जो राजनीतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले थे। राष्ट्रपति की इस घोषणा ने पूरे देश में हलचल मचा दी। विपक्षी दलों ने तुरंत संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां तक कि राष्ट्रपति की अपनी पार्टी, *पीपल्स पावर पार्टी*, ने

AFP

भी इस फैसले का विरोध किया। संसद में विपक्ष ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, और मार्शल लॉ को असंवैधानिक करार दिया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर सेना की गाड़ियों को रोक दिया और बैरिकेड्स को हटाने लगे। लगातार बढ़ते विरोध और संसद में वोटिंग के बाद राष्ट्रपति यून सुक योल को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सुबह 5 बजे उन्होंने मार्शल लॉ खत्म करने की घोषणा की और सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया।

क्या होता है मार्शल लॉ ?

- मार्शल लॉ लागू होने पर सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाती हैं।

- मीडिया और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू होती है।

- किसी भी प्रकार की रैली या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक होती है।

- नियमों के उल्लंघन पर सख्त सजा दी जाती है।

दक्षिण कोरिया में 1980 में आखिरी बार मार्शल लॉ लागू हुआ था, जब जनरल चून डू ह्वान ने सख्त कदम उठाए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की गई थी। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दो-तिहाई यानी 200 सांसदों का समर्थन जरूरी है। हालांकि अभी तक महाभियोग की कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन जनता और विपक्ष ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। इस घटनाक्रम ने दक्षिण कोरियाई राजनीति में राष्ट्रपति यून सुक योल की स्थिति को और अधिक कमजोर कर दिया है।

न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर अमेरिका और कनाडा के 3 पर्वतारोही लापता

इंटरनेशनल डेस्क। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 'आओराकी पर चढ़ाई करने की योजना के तहत रवाना हुए अमेरिका और कनाडा के तीन पर्वतारोही लौटने में नाकाम रहे जिसके कारण उन्हें लापता बताया जा रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 'अमेरिकन माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन की 'वेबसाइट के अनुसार, कोलोराडो के कर्ट ब्लेयर (56) और कैलिफोर्निया के कार्लोस रोमेरो (50) उच पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमाणित 'गाइड हैं। न्यूजीलैंड की पुलिस ने अपने बयान में कनाडा के पर्वतारोही का नाम नहीं बताया, लेकिन उसके परिजन को सूचित करने की जरूरत पर जोर दिया। पुलिस ने बताया कि शनिवार को ये लोग पर्वत पर चढ़ाई शुरू करने के लिए एक शिविर में गए, लेकिन सोमवार को उन्हें लापता बताया गया क्योंकि चढ़ाई के बाद वे पूर्व

निर्धारित परिवहन व्यवस्था के पास नहीं पहुंचे। पुलिस ने कहा कि खोज करने वालों को कुछ घंटों बाद पर्वत पर चढ़ाई से जुड़े कुछ सामान मिले जिसे उन तीनों से संबंधित माना जा रहा है, लेकिन उन तीनों का कोई पता नहीं चला। माउंट कुक के नाम से मशहूर आओराकी में मौसम की स्थिति खराब होने के कारण मंगलवार को खोज अभियान फिर से शुरू नहीं हो सका। यहां भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। दक्षिणी आल्प्स का हिस्सा आओराकी चोटी 3,724 मीटर ऊंची है और इसकी सुंदर तथा बर्फीली पर्वत श्रृंखला न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप तक फैली हुई है। इस पर्वत और इसके आसपास के राष्ट्रीय उद्यान में 20वीं सदी की शुरुआत से अब तक 240 से अधिक मौतें दर्ज की जा चुकी हैं।

बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया, काउंसलर सेवाएं कीं निलंबित

इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश ने मंगलवार को भारतीय उचायुक्त प्रणय वर्मा को यहां विदेश मंत्रालय के कार्यालय में तलब किया। विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में मीडिया को बताया, ''उन्हें (वर्मा को) बुलाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी 'बांग्लादेश संवाद संस्था (बीएसएस) ने कहा कि भारतीय उचायुक्त शाम चार बजे यहां विदेश मंत्रालय पहुंचे। क्क्स्स ने बताया कि कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्ला ने भारतीय उचायुक्त को तलब किया है। पांच अगस्त को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आ जाने के बाद से दोनों पड़ोसियों के संबंधों में तनाव आ गया है, जो पिछले सप्ताह हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गया है।

इसके अलावा बांग्लादेश ने 3 दिसंबर 2024 को अपनी असिस्टेंट हाई कमीशन, अगरतला में सुरक्षा उल्लंघन के बाद वीजा और कांसुलर सेवाएं स्थगित कर दीं। एक भीड़ ने मिशन की सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ दिया था। इसके जवाब में भारतीय अधिकारियों ने सात लोगों को गिरफ्तार किया और इस घटना से जुड़े तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे गंभीर अफसोसजनक घटना बताया। बांग्लादेश मिशन के पहले सचिव मोहम्मद अल-आमीन ने कहा, सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उचायोग में सभी वीजा और कांसुलर सेवाएं तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं।इसी बीच, भारतीय उचायुक्त प्रणय वर्मा को ढाका में बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्ला ने तलब किया। वर्मा ने इस घटना को द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते केवल एक मुद्दे पर आधारित नहीं हो सकते और भारत दोनों देशों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाने का इछुक है। यह बैठक बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा वर्मा को अगरतला घटना पर चर्चा करने के लिए तलब किए जाने के एक दिन बाद हुई। बांग्लादेश के कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरूल ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे भारतीय सरकार की नाकामी बताया। इस बीच, 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, और पिछले हफ्ते हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के बाद यह तनाव और बढ़ गया। 2 दिसंबर को अगरतला में हजारों लोगों ने बांग्लादेश मिशन के सामने प्रदर्शन किया।

क्या है मामला ?

शेख हसीना का भारत दौरा ¬ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हुआ। शेख हसीना के भारत दौरे को लेकर विभिन्न राजनैतिक और कूटनीतिक बयानों ने दोनों देशों के बीच मतभेदों को जन्म दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी¬ इसके बाद बांग्लादेश में एक हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव और बढ़ा, खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े मसलों को लेकर। भारतीय उचायुक्त प्रणय वर्मा को इस घटना के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय तलब किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कूटनीतिक वार्ता की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ट्रंप का टूडो को चौंकाने वाला ऑफर- अगर दिक्कत है तो कनाडा को अमेरिका में मिला दो, 51वां राज्य बना देंगे

इंटरनेशनल डेस्क। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में ट्रूडो को कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा पर टैरिफ का खतरा है, तो वह अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा पर 25त्न टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता था। इस मामले पर चर्चा के लिए ट्रूडो ने ट्रंप से मार-ए-लागो (फ्लोरिडा) में मुलाकात की। ट्रूडो का मकसद टैरिफ के इस खतरे को टालना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत रखना था।

क्या हुआ बातचीत में?

ट्रूडो ने ट्रंप से कहा कि 25त्न टैरिफ लगने से कनाडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो सकती है।

ट्रंप ने पलटकर कहा, कनाडा की अर्थव्यवस्था तब तक जिंदा नहीं रह सकती, जब तक वह अमेरिका को 100 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है।

ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया कि उसने 70 से अधिक देशों के अवैध अप्रवासियों को सीमा पार करने की अनुमति दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग्स और मानव तस्करी रोकने में कनाडा नाकाम रहा है, जिससे अमेरिकी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं।

ट्रंप ने कहा कि कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक है।

उन्होंने यह चेतावनी दी कि अगर ये मुद्दे हल नहीं हुए, तो वह राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के

पहले दिन से ही कनाडा के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लागू कर देंगे।

ट्रंप का विवादित सुझाव

बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि वह अमेरिका का हिस्सा बन जाए। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, *कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। आप (जस्टिन ट्रूडो) गवर्नर बन सकते हैं।* ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री का पद गवर्नर से बेहतर है, लेकिन यह भी बुरा विकल्प नहीं होगा।

ट्रूडो की प्रतिक्रिया

ट्रंप की इस बात पर जस्टिन ट्रूडो और उनके साथ मौजूद अन्य लोग पहले चौंक गए, लेकिन बाद में उन्होंने इसे मजाक मानकर टाल दिया। हालांकि, ट्रूडो ने जोर देकर कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर 25% टैरिफ का असर बहुत गंभीर होगा।

मामले पर लोगों का रिएक्शन

ट्रंप का यह बयान भले ही मजाक में दिया गया हो, लेकिन सोशल मीडिया और विशेषज्ञ इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। - कई लोगों ने इसे कनाडा-अमेरिका संबंधों पर ट्रंप की रणनीतिक सोच का संकेत माना है। वहीं, कुछ ने इसे ट्रंप के अप्रत्याशित बयानबाजी का हिस्सा बताया। यह मुलाकात न सिर्फ टैरिफ और व्यापार घाटे जैसे मुद्दों को उजागर करती है, बल्कि कनाडा-अमेरिका संबंधों की नाजुक स्थिति को भी दिखाती है। ट्रंप की तरफ से दिया गया सुझाव भले ही मजाकिया हो, लेकिन इसके पीछे की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569